प्रत्यक्ष करो के संग्रह पर मास्टर परिपत्र

प्रस्तावना

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) देश के विभिन्न हिस्सों में स्थित आयकर आयुक्तों के माध्यम से विभिन्न प्रत्यक्ष करों के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत आयकर आयुक्तों को आयकर और निगम कर के संग्रह के साथ-साथ वापसी आदी का कार्य सौंपा गया है।

2. प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पी.सी.सी.ए.) केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लेखा संगठन प्रमुख है। विभागीय ढांचे के तहत, पी.सी.सी.ए., सीबीडीटी को प्रत्यक्ष करों से संबंधित सभी प्राप्तियों और धन वापसी के लेखांकन से संबंधित कार्य सौंपे गए हैं। कार्यालय प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक पी.सी.सी.ए. नई दिल्ली में बैठता है और देश भर में क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों (जेडएओ) के माध्यम से संचालित होता है। वर्तमान में विभिन्न स्थानों पर 52 क्षेत्रीय लेखा कार्यालय स्थित हैं।

3. प्रमुख लेखा शीर्ष

आयकर विभाग द्वारा संग्रहण किए गए विभिन्न प्रकार के प्रत्यक्ष करों को निम्नलिखित प्रमुख शीर्षों के तहत वर्गीकृत किया गया है:

i)	निगम कर (सी.टी.)	0020	निगम कर
ii)	आयकर (आई.टी.)	0021	निगम कर के अलावा आय पर अन्य कर
iii)	संपत्ति कर (डब्ल्यू.टी.)	0032	धन पर कर
iv)	उपहार कर (जी.टी.)	0033	गिफ्ट टैक्स

(इस संबंध में और अधिक स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, के लिए, बैंक वेबसाइट www.taxmann.com देख सकते हैं।)

4. 1 अप्रैल 1976 से पहले, आय और अन्य प्रत्यक्ष करों को भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के कार्यालयों, भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखाओं, इसके सहयोगियों द्वारा सरकारी व्यवसाय, कोषागार और उप-कोषागारों का संचालन करने के लिए स्वीकार किया जाता था। जनता के सदस्यों द्वारा इन करों को आसानी से जमा किए जा सकने वाले बिन्दुओं की संख्या बढ़ाने की दृष्टि से, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की शाखाओं के माध्यम से आयकर और अन्य प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए एक योजना 1 अप्रैल 1976 से शुरू की गई थी।

5. 'प्रत्यक्ष करों के लिए लेखा प्रणाली' - संशोधित प्रक्रिया

(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-684/42.01.001/2003-04 दिनांक 9 जनवरी 2004)

लेखांकन और रिपोर्टिंग, प्रेषण में देरी और दस्तावेजों के प्रेषण आदि से संबंधित मुद्दों का अध्ययन करने के बाद, 'सरकारी खातों पर कार्य समूह' ने संशोधित प्रक्रिया का सुझाव दिया जो 1 अक्टूबर 1988 से लागू हुई। रिज़र्व बैंक ने सीबीडीटी बकाया की स्वीकृति पर व्यापक निर्देश जारी किए है और इसका लेखांकन और रिपोर्टिंग अपने प्रकाशन "प्रत्यक्ष करों के लिए लेखा प्रणाली" के माध्यम से किया, जिसे गुलाबी पुस्तिका के रूप में जाना जाने लगा।

6. प्रत्यक्ष करदाताओं के लिए ग्राहक सेवा में सुधार करने की दृष्टि से "प्रत्यक्ष करों की लेखांकन प्रणाली" के निम्नलिखित प्रावधानों पर विशेष ध्यान दिया गया था:

{आरबीआई/2004/135 (डीजीबीए).जीएडी.सं.1142/42.01.001/2003-04) दिनांक 2 अप्रैल 2004}

(i) <u>टोकन जारी करना:</u> यद्यपि भुगतान की प्राप्ति के रूप में पेपर टोकन जारी करने के संबंध में रिज़र्व बैंक द्वारा जारी किए गए निर्देश बहुत स्पष्ट हैं, यह देखा गया है कि कई सारी अधिकृत शाखाएं ऐसे टोकन जारी नहीं करती हैं। कई स्थानों पर, अनौपचारिक व्यवस्थाएं हैं जिसमें करदाता को बैंक शाखाओं से एक विशिष्ट तिथि के बाद चालान संग्रहण करने के लिए कहा जाता है। कुछ मामलों में, रसीदयुक्त चालानों को सुरक्षित रूप से नहीं रखा जाता है और एक खुले बॉक्स में रखा जाता है। ग्राहकों को बिना किसी पहचान के, स्वतंत्र रूप से अपने चालान ले जाने की अनुमति है। चेक या ड्राफ्ट के साथ जमा किए गए चालान के मामले में, रसीद युक्त चालान, चेक या ड्राफ्ट की राशि की भुगतान पर जारी किया जाना है, और इसलिए पेपर टोकन को उस तारीख को इंगित करना चाहिए जिस दिन चालान की रसीद प्रतियां तैयार रखी जाएंगी ताकि करदाता टोकन में दी गई तारीख पर रसीद युक्त चालान को ले जाने की व्यवस्था कर सके।

(ii) <u>रसीद युक्त चालान</u>: स्थानीय समाशोधन व्यवस्था के आधार पर, रसीद युक्त चालान 4-5 दिनों के भीतर करदाता को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निर्धारित प्रतीक्षा अवधि को पार नहीं किया जाना चाहिए और इस संबंध में किसी भी विचलन को रिज़र्व बैंक द्वारा गंभीरता से लिया जाएगा। रसीद प्राप्त चालानों को सावधानीपूर्वक और सुरक्षित तरीके से संभाला जाना चाहिए जब तक कि उन्हें संबंधित पेपर टोकन की प्रस्तुति पर काउंटर पर करदाता को नहीं सौंप दिया जाता है। किसी भी परिस्थिति में, रसीद युक्त चालान को ग्राहकों के लिए सुलभ खुले बॉक्स में नहीं रखा जाना चाहिए।

(iii) <u>रसीद युक्त चालान पर डबल डेट स्टैंप</u>: यह दोहराया जाता है कि, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित पिंक बुकलेट के अनुलग्नक-V में विनिर्दिष्ट अनुसार, चालान पर दो तिथियां, यानी कि चालान और लिखतों की 'जमा की तारीख' और लिखतों की आय की 'वसूली की तारीख' होनी चाहिए।

(iv) <u>समाशोधन चेक की स्वीकृति</u>: यह देखा गया है कि कुछ बैंक, कर प्राप्त करते समय अन्य बैंकों से लिए गए चेक स्वीकार करने के लिए अनिच्छुक होते हैं जिसके परिणामस्वरूप चार्टर्ड एकाउंटेंट/कर सलाहकार अपने ग्राहकों की ओर से अपने स्वयं के चेक प्रस्तुत करते हैं। चूंकि अन्य बैंकों पर तैयार किए गए चेक स्वीकार करने से ग्राहकों को बहुत सुविधा होगी, इसलिए बैंकों को सलाह दी जाती है कि वे उन ग्राहकों को वापस न करें जो अन्य बैंकों पर तैयार किए गए चेक के साथ चालान जमा करते हैं।

(v) <u>क्या करें और क्या न करें</u>: पिंक बुकलेट के अनुबंध-IV में दी गई 'क्या करें और 'क्या न करें' की सूची प्रत्यक्ष कर संग्रह का काम करने वाले बैंक कर्मचारियों को आवश्यकतानुसार प्रदान नहीं की जा रही थी। इसे शाखाओं को जारी किया जा सकता है।

7. <u>ऑनलाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस)</u>

{RBI/2004/131 (DGBA.GAD.No.1008/42.01.034/2003-04) dated April 1, 2004, RBI/2004/145(DGBA.GAD.No.H-1068/42.01.034/2003-04) dated April 16, 2004 & RBI/2004/184 (DGBA.GAD.No.H-1114/42.01.034/2003-04) dated April 29, 2004}

7.1 जनवरी, 2003 में ओएलटीएएस की स्थापना के लिए रिज़र्व बैंक द्वारा एक उच्चाधिकार प्राप्त समिति (एचपीसी) का गठन किया गया था। एचपीसी ने ऑनलाइन कर लेखांकन प्रणाली के लिए लेखांकन प्रक्रिया का सुझाव देने के लिए एक उप-समिति की स्थापना की। सीजीए और सीएजी द्वारा विधिवत अनुमोदित लेखांकन प्रक्रिया को ओएलटीएएस के लिए 01 जून, 2004 से शुरू किया गया था। नई लेखांकन प्रक्रिया (अनुबंध) 16 अप्रैल 2004 को सभी एजेंसी बैंकों को अग्रेषित की गई थी। नई लेखांकन प्रक्रिया की मुख्य विशेषताओं में, करदाता के काउंटरफॉइल के साथ एकल कॉपी चालान की शुरुआत, एकल कॉपी चालान पर चालान पहचान संख्या (सीआईएन) के रूप में जाना जाने वाले अद्वितीय सीरियल नंबर के साथ पावती स्टाम्प की ब्रांडिंग और करदाता के काउंटरफॉइल शामिल हैं। करदाता अब http://tin-nsdl.com पर लॉग इन करके उनके द्वारा भुगतान किए गए कर को देख पा रहे हैं। इसके अलावा, आयकर विभाग द्वारा अपेक्षित नई फाइल संरचना को भी ओएलटीएएस के लिए उपयुक्त सॉफ्टवेयर विकसित करने के लिए एजेंसी बैंकों को अग्रेषित किया गया था।

7.2 नई प्रक्रिया के तहत, बैंकों को सूचित किया गया था कि वे समाशोधन चेक/ड्राफ्ट (यानी नकद और अंतरण चेक/ड्राफ्ट के अलावा) के साथ दिए गए चालानों के संबंध में पावती, ऐसे चेक/ड्राफ्ट की प्राप्ति के बाद ही जारी करें। बैंकों को यह भी सलाह दी गई थी कि वे ऐसे चालानों के संबंध में कागजी टोकन जारी करें जिसमें जमा की

तारीख और उस तारीख को दर्शाया जाए जिस दिन काउंटरफॉइल को सुपुर्दगी के लिए रखा जाएगा। प्राप्तकर्ता बैंकर को सलाह दी गई थी कि वे ऐसे चेक/ड्राफ्ट के भुगतान पर करदाताओं के काउंटरफॉइल का टियर-ऑफ हिस्सा रबर स्टैंप के साथ ब्रांडिंग के बाद वापस कर दें, जिसमें चालान पहचान संख्या (सीआईएन) के साथ भुगतान को स्वीकार किया गया है, जिसमें निम्नलिखित शामिल हैं:

i. बैंक शाखा की बीएसआर कूट संख्या (7 अंक)
ii. चालान प्रस्तुत करने की तिथि (डीडी/एमएम/वाईवाई)
iii. उस दिन उस शाखा में चालान का सीरियल नंबर (5 अंक)

7.3 उसी प्राप्तकर्ता शाखा पर नकदी या चेक के साथ चालान का फाड़ा गया हिस्सा उसी दिन करदाता को ऊपर निर्धारित रबर स्टैंप के साथ ब्रांडिंग करके आवश्यक पावती के साथ वापस किया जा सकता है।

7.4 सभी गैर-कम्प्यूटरीकृत/गैर-नेटवर्क शाखाओं को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि उन शाखाओं से संबंधित डेटा को इनकी निकटतम कम्प्यूटरीकृत/नेटवर्कयुक्त शाखा से नोडल शाखा और नोडल शाखा से लिंक सेल में इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाए ताकि पूरे भारत में बैंक की सभी अधिकृत शाखाओं से संबंधित डेटा एनएसडीएल ई-गवर्नेंस इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा होस्ट किए गए कर सूचना नेटवर्क (टिन) को निर्बाध रूप से प्रेषित किया जा सके।

7.5 यह भी सूचना दी गई थी, आयकर विभाग को स्क्रॉल और चालान भेजने से संबंधित वर्तमान प्रक्रिया को ओएलटीएएस के तहत नई लेखांकन प्रक्रिया प्रतिस्थापित करेगी। यह भी सलाह दी गई कि बैंकों को अग्रेषित ओएलटीएएस लेखांकन प्रक्रिया में प्रस्तावित परिवर्तनों को छोड़कर, पिंक बुकलेट "प्रत्यक्ष करों की लेखांकन प्रणाली" (30 जून, 1999 तक अद्यतन) में निहित अनुदेश लागू रहेंगे।

7.6 इसके अलावा, जेडएओ और आयकर विभाग को पेपर स्क्रॉल और चालान भेजने की सामान्य प्रथा के अलावा टिन को ऑनलाइन डेटा प्रसारित करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया गया।

7.7 बैंकों को यह सुझाव दिया गया था कि नागपुर में स्थित उनके लिंक सेल को मुंबई में टिन (एनएसडीएल) से एक समर्पित लीज लाइन के साथ जोड़ा जा सकता है ताकि सुरक्षित दो तरफा संचार सुनिश्चित किया जा सके।

8. एनएसडीएल को डेटा का प्रसारण - सत्यापन जांच

{आरबीआई/2004/75(डीजीबीए).जीएडी.सं.एच-69/42.01.034/2004-05) दिनांक 28 जुलाई, 2004, डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-8649/42.01.034/2005-06 दिनांक 23 दिसम्बर, 2005}

8.1 बैंकों द्वारा अपलोड किए गए आंकड़ों में एनएसडीएल/आयकर विभाग द्वारा पाई गई विभिन्न प्रकार की त्रुटियों की सूचना बैंकों को दी गई है। विशेष रूप से, पैन/टैन नंबर के संबंध में पाई गई डेटा एंट्री त्रुटियां, गलत नोडल स्क्रॉल शाखा डेटा, आकलन वर्ष, अनुपस्थिति या गलत करदाता का नाम, सीआईएन नंबर व प्रमुख शीर्ष कोड और राशि संबंधी त्रुटियाँ बैंकों के ध्यान में लाई गई थी।

8.2 पाई गई विसंगतियों को दूर करने के लिए, यह निर्णय लिया गया है कि प्रत्येक बैंक सभी प्रकार के रिकॉर्ड के लिए ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में तत्काल प्रभाव से निम्नलिखित सत्यापन जांच शामिल करेगा:

(i) RT01 और RT06 में फ़ील्ड NOD_BR_COL_SC_DT और NOD_BR_PYMT_SC_DT के लिए मान क्रमशः 01-06-04 और ट्रांसमिशन की तारीख (यानी फ़ाइल नाम) के बीच होना चाहिए।

(ii) पैन/टैन, 10 अल्फान्यूमेरिक वर्णों से कम का नहीं हो सकता है। यदि इसकी लंबाई 10 है तो पैन के मामले में पैन का पहला पांच और दसवां वर्ण केवल अल्फा होना चाहिए, और छठे से नौवें यानी अगले चार संख्यात्मक होना चाहिए। टैन के मामले में पहले तीन वर्ण सीटीयू कोड होने चाहिए और चौथे, दसवें को अल्फा होना चाहिए और अगले पांच (पांचवें से नौवें) को संख्यात्मक होना चाहिए। पैन/टैन का उल्लेख 1 जनवरी, 2005 से अनिवार्य कर दिया गया है।

(iii) नाम का फ़ील्ड हमेशा अनिवार्य होता है और इसमें केवल अल्फ़ान्यूमेरिक और डॉट्स का संयोजन होना चाहिए और यह एक से अधिक वर्णों का होना चाहिए (नाम स्ट्रिंग, डॉट्स और संख्याओं या दोनों की नहीं होनी चाहिए, मुख्य स्ट्रिंग में वर्णों का होना आवश्यक है) चालान पर पैन/टैन का उल्लेख किए जाने के बावजूद करदाता का **पूरा नाम** प्रेषित करना अनिवार्य है।

(iv) एक संग्रह शाखा का जेडएओ कोड नंबर स्थायी है और जेडएओ कोड नंबर का विवरण रिज़र्व बैंक द्वारा प्रकाशित गुलाबी पुस्तिका में उपलब्ध है। नोडल शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि यह जेडएओ कोड नंबर, रिकॉर्ड टाइप 01 में सही ढंग से उल्लिखित है और किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं किया गया है। यह सूचित किया जाता है कि सभी बैंकों को अपने ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में जेडएओ क्षेत्र में कोड को सहेजना चाहिए क्योंकि ऐसे उदाहरण आरबीआई / सरकार के ध्यान में लाए गए हैं, जहां एक ही शाखा ट्रांसमिशन की विभिन्न तिथियों पर अलग-अलग जेडएओ कोड का उल्लेख कर रही है।

8.3 उपर्युक्त सत्यापन जांचों के अतिरिक्त, बैंकों द्वारा निम्नलिखित पर्यवेक्षी कदम उठाए जाने हैं:

(i) संग्रहणकर्ता शाखाओं के शाखा प्रबंधकों को चालान से कैप्चर किए गए नाम और राशि की शुद्धता सुनिश्चित करनी चाहिए। इसके लिए सभी बैंक शाखाओं में डाटा एंट्री की 'मेकर-चेकर' प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए।

(ii) सभी संग्रहणकर्ता शाखाओं को अनिवार्य रूप से रिकॉर्ड टाइप 01 और रिकॉर्ड टाइप 02 (सारांश रिकॉर्ड) को प्रसारित करना होगा, यदि उस दिन संग्रहण होता है। जिन शाखाओं में दिन के दौरान कोई संग्रहण नहीं हुआ है, वहां रिकॉर्ड टाइप 02 (शून्य विवरण) नोडल शाखा को प्रेषित किया जाना है। इससे टिन उचित रूप से ओएलटीएएस के कार्यान्वयन की निगरानी कर सकेगा।

(iii) नोडल शाखा स्तर पर यह सुनिश्चित करने के लिए पर्यवेक्षण किया जाना चाहिए कि सभी संग्रहणकर्ता शाखाएं रिकॉर्ड टाइप 01 और रिकॉर्ड टाइप 02 को प्रसारित कर रही हैं। उन्हें यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि जो शाखाएं संग्रहण कर रहे हैं जिनके पास कोई संग्रह नहीं है। वे MAJ_HD_CD =0 और TOT_AMT = 0 के साथ केवल रिकॉर्ड टाइप 02 (शून्य विवरण) को उनकी संबंधित नोडल शाखा को प्रेषित करें।

(iv) नोडल शाखा के शाखा प्रबंधक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जेडएओ को प्रस्तुत किसी विशेष तिथि के नोडल शाखा स्क्रॉल में दिखाया गया प्रमुख शीर्षवार संग्रहण, टिन को प्रस्तुत करने के लिए लिंक सेल को प्रेषित ओएलटीएएस डेटा में संबंधित योग के अनुरूप हो। यह प्रक्रिया 1 जून, 2004 से सभी भुगतानों के संबंध में की जानी चाहिए।

(v) लिंक सेल स्तर पर सभी बैंकों को टिन को प्रेषित त्रुटि रिकॉर्ड पर की गई कार्रवाई का त्रुटि रिकॉर्ड बनाए रखना चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कुछ कमियों के कारण टीआईएन द्वारा शुरू में अस्वीकृत किए गए सभी अभिलेखों को 48 घंटों के भीतर कमियों को दूर करने के बाद अनिवार्य रूप से टिन में पुनः प्रेषित किया जाए।

(vi) यह देखा गया है कि बैंक गलत प्रमुख शीर्ष कोड दर्ज कर रहे हैं यानी निगम कर के लिए प्रमुख शीर्ष 020 या निगम कर के अलावा आयकर के लिए प्रमुख शीर्ष 021 के तहत प्राप्त भुगतानों को बदल रहे हैं। इससे भुगतानों का गलत वर्गीकरण होता है और आयकर विभाग और जेडएओ के बीच खातों के मिलान को प्रभावित करता है। वैध पैन के मामले में, उपरोक्त सत्यापन को ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में लागू किया जा सकता है यानी यदि 4$^{वां}$ वर्ण (बाईं ओर से) 'सी' है तो प्रमुख शीर्ष कोड 020 होना चाहिए।

8.4 आयकर विभाग ने हमें यह भी सूचित किया है कि आकलन वर्ष के आंकड़ों को प्रसारित करते समय, बैंकों को सामान्य और ब्लॉक आकलन वर्षों के लिए पहले भाग को प्रेषित करने की आवश्यकता थी; उदाहरण के लिए सामान्य आकलन वर्ष 2005-2006 के लिए बैंक को 2005 को प्रेषित करना आवश्यक है और 1997-2005 जैसे ब्लॉक आकलन वर्ष के लिए वर्ष 1997 के आंकड़ों को प्रेषित किया जाना चाहिए।

9. ZAOs को ई-मेल द्वारा दैनिक स्क्रॉल भेजना

{आरबीआई/2006/295 (डीजीबीए) जीएडी.संख्या एच-11140/42.01.034/2005-06) दिनांक 2 फरवरी, 2006}

बैंकों को प्रत्यक्ष कर संग्रह के लिए इलेक्ट्रॉनिक नोडल शाखा दैनिक मुख्य स्क्रॉल के संशोधित प्रारूप की सूचना दी गई थी। संशोधित प्रारूप **(अनुबंध III)** का उपयोग सभी प्राप्त शाखाओं से भौतिक चालान/स्क्रोल की प्राप्ति लंबित होने तक सभी जेडएओ को इलेक्ट्रॉनिक रूप से दैनिक मुख्य स्क्रॉल भेजने के लिए किया जाना है।

10. सीबीडीटी बकाया के संग्रहण के लिए उप-एजेंसी व्यवस्था का उन्मूलन

{आरबीआई/2004/326(डीजीबीए).जीएडी.सं.3278-3311/42.01.034/2004-05) दिनांक 31 दिसम्बर, 2004}

यह देखा गया कि ओएलटीएएस के तहत डेटा अपलोड नहीं करने के प्रमुख कारणों में से एक इलाके में एक अन्य प्रमुख बैंक के साथ उप-एजेंसी व्यवस्था का अस्तित्व है, जहां संबंधित उप-एजेंसी बैंक के पास सीबीडीटी द्वारा निर्धारित मानदंड के अनुसार अपनी नोडल शाखा रखने के लिए पर्याप्त संख्या में शाखाएं नहीं हैं। संगतता न होने या अन्य कारणों से उप-एजेंसी व्यवस्था के तहत शाखाओं द्वारा एकत्रित किए गए चालानों के संबंध में डेटा कई मामलों में प्रधान एजेंसियों के बैंकों द्वारा टिन पर अपलोड नहीं किया गया था। उप-एजेंसी व्यवस्थाओं से उत्पन्न होने वाली देरी और समस्याओं से बचने के लिए, आयकर निदेशालय (प्रणाली), नई दिल्ली के परामर्श से उप-एजेंसी व्यवस्था को पूरी तरह से समाप्त करने का निर्णय लिया गया है। बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी नोडल शाखाएं नामित करें जहां भी उनकी शाखाएं उप-एजेंसी व्यवस्थाओं के तहत कार्य कर रही हैं।

11. निधियों का निपटान - आरबीआई, सीएएस नागपुर को रिपोर्ट करना

{आरबीआई/2005/466 (डीजीबीए.जीएडी. सं.एच.5801/42.01.034/2004-05) दिनांक 13 मई, 2005 और भारतीय रिज़र्व बैंक/2005/406 (डीजीबीए जीएडी.सं.एच.5236/42.01.034/2004-05) दिनांक 29 मार्च, 2005}

11.1 दिनांक 1 अप्रैल, 2005 से टिन पर अपलोड किए गए ऑन लाइन आंकड़ों के आधार पर निधियों के निपटान के निर्णय को ध्यान में रखते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के लेन-देनों की सूचना भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर को देने की मौजूदा प्रणाली की समीक्षा की गई है। तदनुसार, यह निर्णय लिया गया कि एजेंसी बैंक सीबीडीटी के आंकड़े आरबीआई, सीएएस, नागपुर को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-मेल (द्वितीय श्रेणी प्रमाण पत्र धारक द्वारा हस्ताक्षरित) के माध्यम से अलग से प्रस्तुत करेंगे। सीबीडीटी के आंकड़ों के अनुसार सप्ताह के दिनों में 13.15 बजे और शनिवार को दोपहर 12.30 बजे के आंकड़े डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित ई-मेल के माध्यम से धन निपटान के लिए सीएएस, नागपुर को एक साथ रिपोर्ट किए जाएंगे। निर्धारित समय के बाद मेल किए गए डेटा को सीएएस, नागपुर द्वारा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा।

11.2 बैंकों को सूचित किया गया था कि भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस की प्रणाली द्वारा अस्वीकृति किसी भी आंकड़ों का हिसाब उसी दिन नहीं दिया जाएगा जिस दिन लिंक सेल से संशोधित सलाह प्राप्त करने के बाद वर्तमान में ऐसा किया जा रहा है। सीएएस में प्रणाली द्वारा स्वीकार किए गए आंकड़ों का हिसाब रखा जाएगा। अस्वीकृति रिपोर्ट उसी दिन दैनिक इनपुट स्टेटमेंट के साथ लिंक सेल को दी जाएगी। बैंकों को इस संबंध में अपनी शाखाओं और लिंक सेल को आवश्यक अनुदेश जारी करने की सलाह दी गई थी।

11.3 यह स्पष्ट किया गया कि धन निपटान के लिए किसी भी तारीख को सीएएस, नागपुर में अपलोड की गई वित्तीय डेटा फाइल और टिन पर अपलोड की गई उस विशेष निपटान तिथि से संबंधित चालान डेटा बिल्कुल मेल खाना चाहिए। एनएसडीएल द्वारा बाद में अस्वीकार की गई फाइलें, यदि कोई हों, सत्यापन त्रुटियों आदि के कारण अलग से संसाधित की जानी चाहिए और पुनः अपलोड की जानी चाहिए। बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि करदाता द्वारा जमा किए गए प्रत्येक चालान के संबंध में चालान डेटा अपलोड किया गया है और टिन द्वारा विधिवत स्वीकार किया गया है। टिन में फाइलों को दोबारा अपलोड करने से फंड निपटान डेटा पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लिंक सेल से सीएएस, नागपुर को जाने वाले डेटा और टिन में जाने वाले सापेक्ष

चालान डेटा को एक साथ अपलोड किए जाने पर ही टिन को की गई रिपोर्टिंग पूर्ण रिपोर्टिंग मानी जाएगी।

11.4 लिंक सेल को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि किसी दी गई अपलोडिंग तिथि के लिए सीएएस और टिन पर अपलोड किए गए आंकड़ों में कोई विसंगति न हो।

11.5 नोडल शाखाओं को ऑन-लाइन कर लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया के पैरा 6 में निहित अनुदेशों का सावधानीपूर्वक पालन करने और संबंधित क्षेत्रीय लेखा कार्यालयों को दैनिक आधार पर स्क्रॉल और चालान आदि भेजने की सूचना भी दी गई थी।

12. ओएलटीएएस के संबंध में बैंकों को मार्गदर्शन के लिए आरबीआई द्वारा जारी किए गए कतिपय स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं:
{आरबीआई/2004/213 (डीजीबीए).जीएडी.दिनांक 22 मई, 2004 और भारतीय रिज़र्व बैंक/2004/181 (डीजीबीए) दिनांक 22 मई, 2004(डीजीबीए) संख्या एच-1169/42.01.034/2003-04.जीएडी.सं एच-235/42.01.034/2004-05) दिनांक 15 सितम्बर 2004}

12.1 चालान पहचान संख्या (सीआईएन)

यह स्पष्ट किया गया कि ओएलटीएएस लेखांकन प्रक्रिया (अनुबंध) के पैरा 1.3.3 के अनुसार सभी चालानों के लिए सीरियल क्रमांक देना होगा। नकद के साथ, चेक ट्रांसफर करने **के साथ-साथ** सभी प्रकार के प्रत्यक्ष करों में एक विशेष दिन पर चेक क्लियर करना। जबकि नकद और हस्तांतरण चेक (यानी संग्रहणकर्ता शाखा पर तैयार किया गया चेक) के साथ दिए गए चालान के आंसू-बंद हिस्से को जमाकर्ता को जमा की तारीख, बीएसआर कोड और सीआईएन आदि को इंगित करते हुए निर्धारित रबर स्टैंप के साथ वापस करने की आवश्यकता होती है, लेकिन समाशोधन चेक (यानी अन्य शाखाओं / बैंकों पर तैयार) के साथ दिए गए चालान को केवल लिखत की प्राप्ति पर वापस करना होगा। प्राप्त करने वाले बैंक शाखा के अधिकृत अधिकारी को भी चालान के टियर-ऑफ हिस्से के साथ-साथ मूल चालान पर हस्ताक्षर करने की आवश्यकता थी।

12.2 बैंकों से अनुरोध किया गया था कि वे ओएलटीएएस पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) के लिए आयकर वेबसाइट www.incometaxindia.gov.in देखें।

13. इसके अलावा, बैंकों को अधिकृत शाखाओं की पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई थी कि प्रत्येक चालान रिकॉर्ड प्रत्येक शाखा द्वारा टिन को प्रेषित किया जाए जहां कर संग्रह किया गया है। यह दोहराया गया कि जब दिन के दौरान कोई कर संग्रह नहीं हुआ हो तो नोडल शाखा को एक शून्य विवरण (रिकॉर्ड प्रकार 02) भेजा जाए ताकि टिन ओएलटीएएस की समुचित निगरानी की जा सके। इस बात पर भी जोर दिया गया कि टिन को प्रेषित डेटा सही और पूर्ण होना चाहिए और निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुरूप होना चाहिए।

14. बैंकों को, आयकर निदेशालय द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक के ध्यान में लाई गई, निम्नलिखित गंभीर कमियों के बारे में सूचित किया गया था:

{आरबीआई/2004/164 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच-170/42.01.034/2003-04) दिनांक 4 सितम्बर, 2004}

14.1 **बैंकों द्वारा पैन/टैन को उचित रूप से दर्ज नहीं किया जाना** - कई केंद्रों से यह सूचना प्राप्त हुई कि जहां करदाता ने अपने पैन को सही तरीके से उद्धृत किया है, वहां भी कुछ बैंक शाखाएं या तो इसे दर्ज नहीं कर रही थीं या इसे अधूरे तरीके से दर्ज कर रही थीं। इस संबंध में, बैंकों को सलाह दी गई थी कि ऑन-लाइन टैक्स लेखांकन प्रणाली (ओएलटीएएस) प्रक्रिया/नियमों के तहत, यह निर्धारित किया गया था कि जहां भी *करदाता द्वारा उचित अल्फा न्यूमेरिक संरचना में 10 अंकों का पैन/टैन उद्धृत किया जाता है, बैंकों को पैन और करदाता का नाम अधिग्रहण करना होगा, न कि पता।.*

14.2 **करदाता के पूरे नाम का कैप्चर न होना** - टिन पर अपलोड किए गए डेटा के अवलोकन से संकेत मिलता है कि कई बैंक शाखाएं अभी भी करदाता के नाम कॉलम में एक या दो अक्षर डाल रही हैं। कुछ मामलों में प्रतीकों और बिंदुओं का भी उपयोग किया गया था। बैंक कृपया ओएलटीएएस डेटा में करदाता का पूरा

नाम दर्ज किया जाना सुनिश्चित करें।

14.3 गलत पता फ़ील्ड - विश्लेषण किए गए डेटा से यह भी पता चलता है कि कई बैंक शाखाओं द्वारा पता फ़ील्ड को सही पता विवरण दर्ज नहीं किया जा रहा था। कई मामलों में, केवल कुछ यादृच्छिक वर्णमाला या संख्याएं दर्ज की जा रही थीं जो फिर से संकेत देती हैं कि बैंक शाखाएं पूर्ण विवरण दर्ज करने पर गौर नहीं कर रही थीं। आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए बैंकों को सलाह दी गई थी।

14.4 चालान पहचान संख्या (सीआईएन) की गलत रिपोर्टिंग – यह देखा गया कि कुछ बैंक शाखाएं करदाता के काउंटरफॉइल पर एक विशेष चालान पहचान संख्या (सीआईएन) आवंटित कर रही थीं, लेकिन भेजे गए ओएलटीएएस डेटा पर एक अलग सीआईएन दर्ज कर रही थीं। ओएलटीएएस प्रक्रिया/नियमों के अनुसार, सीआईएन को केवल प्रस्तुतीकरण की तारीख पर आवंटित किया जाना था। करदाता के काउंटरफॉइल के साथ-साथ चालान के मुख्य निकाय पर अंकित सीआईएन नंबर को टिन में प्रेषित किया जाना चाहिए।नियमों के अनुसार, किसी विशेष दिन के लिए नोडल शाखा का स्क्रॉल जेडएओ दोनों के साथ-साथ ओएलटीएएस से टिन में प्रेषित डेटा के लिए समान होना चाहिए। यह स्पष्ट किया गया कि जेडएओ और टिन को एक दिन के लिए भेजे जा रहे सभी संग्रह डेटा चालान की संख्या और प्रमुख शीर्ष दोनों के संबंध में मेल खाने चाहिए। इसके अलावा बैंकों को यह सुनिश्चित करने की सलाह दी गई कि **प्रत्येक** चालान रिकॉर्ड प्रत्येक शाखा द्वारा टिन को भेजा जाए जहां संग्रह किया गया है।

15. प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए बैंक शाखाओं का अधिकार रद्द

{आरबीआई/2005/412 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच.5318/42.01.034/2004-05) दिनांक 4 अप्रैल, 2005}

15.1 ओएलटीएएस के तहत प्राधिकृत बैंक शाखाओं की सूचीबद्धता समाप्त करने की प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने की दृष्टि से प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआरसीसीए), सीबीडीटी, नई दिल्ली के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि शाखाओं के प्राधिकार रद्द करने का कोई भी प्रस्ताव एजेंसी बैंकों के प्रधान कार्यालयों द्वारा भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। केंद्रीय कार्यालय निम्नलिखित मापदंडों /दिशानिर्देशों को ध्यान में रखते हुए:

i) मौजूदा शाखा को पिछले वर्ष (अप्रैल-मार्च) में कोई प्रत्यक्ष कर प्राप्त नहीं हुआ है।

ii) प्राधिकृत शाखा की सूचीबद्धता समाप्त करने के प्रस्ताव को संबंधित बैंक के शीर्ष प्रबंधन का अनुमोदन प्राप्त है।

15.2 भारतीय रिज़र्व बैंक/पी.सी.सी.ए., सीबीडीटी के कार्यालय द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किए जाने के बाद संबंधित बैंक को इस आशय का व्यापक प्रचार करना चाहिए कि विशिष्ट शाखा एक विशिष्ट पूर्वावलोकन तिथि से करों की स्वीकृति बंद कर देगी और तदनुसार हमें सूचित करें।

16. कर सूचना नेटवर्क द्वारा विकसित फ़ाइल पृथक्करण यूटिलिटी

{आरबीआई/2005/81 (डीजीबीए).जीएडी.सं.382/42.01.034/2005-06) दिनांक 26 जुलाई, 2005}

कुछ बैंकों से अनुरोध प्राप्त हुए हैं कि कर सूचना नेटवर्क (टिन) को कुछ गलत रिकॉर्ड के कारण बैंक के लिंक सेल से प्राप्त ओएलटीएएस डेटा की पूरी फाइल को अस्वीकार नहीं करना चाहिए। बैंकों ने इच्छा व्यक्त की है कि टीआईएन को गलत रिकॉर्ड को अस्वीकार करते हुए उन अभिलेखों को स्वीकार करना चाहिए जो सही सत्यापन के साथ हैं। एनएसडीएल (टिन) और बैंकों के साथ सीबीडीटी की चर्चा के आधार पर, टिन ने एक फाइल पृथक्करण यूटिलिटी विकसित की थी जिसे बैंकों को सलाह दी गई थी। (अनुबंध II)

17. सीबीडीटी संग्रहों को सरकारी खातों को सौंपने से संबंधित लेखा प्रक्रिया – सार्वजनिक क्षेत्र के एजेंसी बैंक

{आरबीआई/2005/411 (डीजीबीए).जीएडी.दिनांक 1 अप्रैल, 2005, भारतीय रिज़र्व बैंक/2006/150 (डीजीबीए) दिनांक 1 अप्रैल, 2005 को एच-5287/42.01.034/2004-05.जीएडी.दिनांक 10 अक्तूबर, 2006 और भारतीय रिज़र्व बैंक/2007/235 (डीजीबीए) की संख् या एच-6226/42.01.011/2006-07. जीएडी. दिनांक 24 जनवरी, 2007, भारतीय रिज़र्व बैंक/2007/286 (डीजीबीए) दिनांक 24 जनवरी, 2007 को एच-11763/42.01.011/2006-07.जीएडी. सं.13742/42.01.011/2006-07) दिनांक 13 मार्च, 2007}

17.1 भारत सरकार के परामर्श से यह निर्णय लिया गया है कि 1 अप्रैल 2005 से टी +3 दिनों (रविवार और छुट्टियों सहित) के बजाय टी + 3 कार्य दिवसों (जहां टी वह दिन है जब बैंक शाखा को पैसा उपलब्ध होता है) में कर संग्रह जमा करने के लिए अनुमत अधिकतम दिनों से संबंधित अनुदेशों में संशोधन किया जाए। कार्य दिवसों की गणना के लिए सीएएस, नागपुर की अवकाश सूची मान्य होगी।

17.2 यह तय किया गया है कि भारतीय रिज़र्व बैंक के सीएएस के साथ निपटान की तारीख को टी+3 कार्य दिवसों की मौजूदा समय सीमा से बाहर रखा जाएगा।

17.3 विलंबित अवधि के लिए बैंकों पर ब्याज लगाया जाएगा न कि लेनदेन की तारीख से। दूसरे शब्दों में, 'लंबित अवधि' का आकलन पुट थ्रू डेट के बाद के दिन से शुरू होगी।

17.4 1 लाख रुपये और उससे अधिक के लेनदेन में लंबित अवधि पर बैंक दर + 2% पर विलंबित अवधि ब्याज लगेगा। बैंक दर वह दर होगी जिसे आरबीआई द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जा रहा है।

17.5 1 लाख रुपये से कम के लेनदेन के लिए, विलंबित अवधि ब्याज बैंक दर पर 5 कैलेंडर दिनों तक और 5 कैलेंडर दिनों से अधिक की लंबित अवधि के लिए बैंक दर + 2% **की दर से लगाया जाएगा।** बैंक दर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अधिसूचित दर होगी जो लेनदेन के समय लागू होती है।

17.6 महालेखा नियंत्रक द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि मंत्रालयों/विभागों के प्रत्येक प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक (पीआर सीसीए), मुख्य लेखा नियंत्रक (सीसीए) और लेखा नियंत्रक (सीए) बैंकों द्वारा किए गए सभी विप्रेषणों की तिमाहीवार समीक्षा करेंगे। यदि बैंक के साथ या उसकी किसी भी शाखा के साथ लगातार दो तिमाहियों में 5% या उससे अधिक की देरी पाई जाती है, तो संबंधित बैंक या शाखा के लिए प्राधिकरण की समीक्षा के लिए पीआरसीए/सीसीए/सीए की सिफारिशों के साथ सीजीए को भेज दिया जाएगा। बैंकों से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने स्वयं के आंतरिक नियंत्रण तंत्र का निर्माण करें ताकि बैंक द्वारा अपनी शाखाओं के लिए निवारक और सुधारात्मक कार्रवाई समय पर की जा सके।

18 सीबीडीटी संग्रहों को सरकारी खातों- निजी क्षेत्र की एजेंसी बैंक में जमा करने से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया –।

18.2 निजी क्षेत्र की एजेंसी बैंकों के मामले में सीएएस, नागपुर के साथ लेनदेन को निपटाने की समय सीमा **टी + 3 दिन (रविवार और छुट्टियों सहित)** बनी रहेगी। विलंब की अवधि को प्राप्तकर्ता शाखा में संग्रह प्राप्त होने की तारीख (बैंक में धन की वास्तविक वसूली) से गिना जाएगा जब तक कि सरकारी खाते में क्रेडिट के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक, सीएएस, नागपुर को सूचित नहीं किया जाता है। विलंबित अवधि ब्याज बैंकों से वसूला जा सकता है, चाहे इसमें कितनी भी राशि शामिल हो। विलंबित अवधि ब्याज प्रचलित बैंक दर + 2% पर लगाया जाएगा। (बैंक दर समय-समय पर आरबीआई द्वारा अधिसूचित की जाएगी)।

18.3 इसके अलावा, उपर्युक्त पैरा 17.6 में दिए गए अनुदेश निजी क्षेत्र के एजेंसी बैंकों के लिए भी लागू होंगे।

19 करदाताओं द्वारा चेक का आहरण- भुगतानकर्ता का नाम

(डीजीबीए.जीएडी.सं.एच-8294/42.01.037/2005-06 दिनांक 14 दिसम्बर, 2005)

ओएलटीएएस के तहत प्रत्यक्ष कर भुगतान के लिए चालान जमा करने के लिए करदाताओं द्वारा चेक/डीडी आहरित करते समय भुगतानकर्ता के नाम में एकरूपता प्राप्त करने की दृष्टि से आयकर विभाग द्वारा आयकर चालान के पीछे निम्नलिखित अनुदेश मुद्रित करने का निर्णय लिया गया है-

करदाता आयकर के भुगतान के लिए चेक/डीडी जारी कर सकते हैं:

"..... (उस बैंक का नाम जहां चालान जमा किया जा रहा है) - आयकर खाता में भुगतान करें"। बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे इस बदलाव को अपनी सभी प्राधिकृत शाखाओं के संज्ञान में लाएं।

20 प्रमुख शीर्ष / चालान

{आरबीआई/2005/39 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच-42/42.01.034/2005-06) दिनांक 4 जुलाई, 2005}

बैंकों को भारत सरकार द्वारा शुरू किए गए संशोधित चालान प्रारूपों के बारे में सूचित किया गया था, जो दो नए करों अर्थात् अनुषंगी लाभ कर (**फ्रिंज बेनिफिट टैक्स)** और **बैंकिंग नकद लेन-देन कर** के परिचय के कारण आवश्यक थे। आयकर विभाग द्वारा प्रमुख लेखा शीर्षों और उप-लघु लेखा शीर्षों के लिए किए गए परिवर्तन/युक्तिकरण नीचे दिए गए हैं:

चालान संख्या आईटीएनएस - 280

उक्त चालान (ए) कंपनियों पर 0020 आयकर (निगम कर) और (बी) 0021 आयकर (कंपनियों के अलावा) जैसे दो प्रमुख शीर्षों के तहत भुगतान के लिए। करदाताओं के लिए अब लगातार आकलन वर्षों के अलावा अन्य आकलन वर्षों के लिए करों का भुगतान करना संभव होना चाहिए। उदाहरण के लिए, ब्लॉक अवधि (लगातार एक से अधिक मूल्यांकन वर्ष) के लिए आकलन के मामले में, बैंक के सॉफ्टवेयर में मूल्यांकन वर्ष क्षेत्र को लगातार मूल्यांकन वर्ष के अलावा किसी अन्य अवधि के लिए, उदाहरण के लिए मूल्यांकन वर्ष 1991-97, 1992-99, 1993-99 के लिए भुगतान आदि, भुगतान स्वीकार करने के लिए संशोधित किया जा सकता है।

चालान सं. 281

चालान टीडीएस (स्रोत पर कर कटौती)/टीसीएस (स्रोत पर कर संग्हीत कर) के भुगतान के लिए है। इसमें दो प्रमुख शीर्ष हैं यानी (ए) कंपनी कटौतीकर्ताओं के लिए 0020 और (बी) गैर-कंपनी कटौतीकर्ताओं के लिए 0021। चालान में दो लघु शीर्ष कोड होते हैं, जिन्हें करदाता द्वारा टिक किया जाता है (ए) करदाता द्वारा देय टीडीएस /टीसीएस (लघु शीर्ष -200) (बी) नियमित मूल्यांकन पर टीडीएस / टीसीएस (आयकर विभाग द्वारा उठाया गया) (लघु शीर्ष - 400)।

चालान में अब पेश किए गए नए तीन अंकों के कोड उप - लघु शीर्ष निम्नानुसार हैं:

अनुभाग	भुगतान की प्रकृति	कोड
206सी	मानव उपभोग के लिए मादक शराब से स्रोत पर संग्रह	6 सी ए
206सी	वन पट्टे के तहत प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रह	6सी बी
206सी	वन पट्टे के अलावा किसी अन्य माध्यम से प्राप्त लकड़ी से स्रोत पर संग्रह	6 सी सी
206सी	किसी अन्य वन उपज से स्रोत पर संग्रह (तेंदू पत्ते नहीं)	6 सी डी
206सी	स्क्रैप से स्रोत पर संग्रह	6 सी ई
206सी	ठेकेदारों या लाइसेंसधारक से स्रोत पर संग्रह या पार्किंग स्थल से संबंधित पट्टे	6सी एफ
206सी	ठेकेदारों या लाइसेंसधारक से स्रोत पर संग्रह या टोल प्लाजा से संबंधित पट्टे	6सी जी
206सी	ठेकेदारों या लाइसेंसधारक से स्रोत पर संग्रह या खदान या खदान से संबंधित पट्टे	6 सी एच
206सी	तेंदू पत्तों से स्रोत पर संग्रह	6 सी आई

चालान संख्या 282

यह चालान कई करों के भुगतान के लिए है। इस चालान में किए गए परिवर्तन निम्नानुसार हैं:

a) प्रतिभूति लेनदेन कर को पहले के प्रमुख शीर्ष 0025 के स्थान पर प्रमुख शीर्ष 0034 के रूप में फिर से संख्या दी गई है।

b) संपत्ति-कर - इस चालान में प्रमुख शीर्ष 0032 को शामिल किया गया है। इससे पहले यह प्रमुख शीर्ष चालान नंबर 280 में था।

चालान संख्या 283

आकलन वर्ष 2010-11 से अनुषंगी लाभ कर ***को समाप्त करने और 1 अप्रैल, 2009 से बैंकिंग नकद लेनदेन कर की वापसी के परिणामस्वरूप, यह चालान वर्तमान में उपयोग में नहीं है।***

बैंक कृपया ओएलटीएएस सॉफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन की व्यवस्था कर सकते हैं और उपरोक्त परिवर्तनों को प्रत्यक्ष कर संग्रहणकर्ताशाखाओं के ध्यान में ला सकते हैं ताकि शाखाएं तत्काल प्रभाव से इन करों का भुगतान स्वीकार कर सकें।

21 पैन/टैन का सत्यापन

{आरबीआई/2006/55 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच-161/42.01.034/2005-06) दिनांक 7 जुलाई, 2006}

यह निर्णय लिया गया है कि आयकर विभाग अपने क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र के माध्यम से सभी एजेंसी बैंकों की नोडल शाखाओं को पैन/टैन मास्टर और उस क्षेत्र के करदाताओं के नाम वाली एक सीडी प्रदान करेगा, जिसे तिमाही आधार पर अघतित किया जाएगा। बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी शाखाओं को आंतरिक वितरण के लिए सीडी की प्रतियाँ एक सरल डेटा पुनर्प्राप्ति सॉफ्टवेयर के साथ बनाएं, जिसका उपयोग चालान जमा में करदाता द्वारा उद्धृत पैन /टैन को पुनःसत्यापितकरने के लिए किया जा सकता है। प्रवेश प्रणाली स्वचालित रूप से पैन / टैन की अलग डेटा प्रविष्टि को समाप्त कर देती है। यदि करदाता का पैन/टैन सीडी में उपलब्ध नहीं है, तो ग्राहक से अनुरोध किया जा सकता है कि वह पैन/टैन की शुद्धता को इंगित करने के लिए संबंधित पैन/टैन कार्ड या किसी अन्य दस्तावेज की एक प्रति प्रस्तुत करे। बैंकों को उन मामलों में सत्यापन के प्रयोजनार्थ उपयोग किए जाने वाले इन दस्तावेजों को अपने पास रखने की आवश्यकता नहीं है जहां कर दाता का पैन/टैन क्षेत्रीय कंप्यूटर केंद्र द्वारा प्रदान की गई सीडी में उपलब्ध नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे संबंधित प्राप्तकर्ता अधिकारी द्वारा प्रत्यक्ष जांच के बिना चालान स्वीकार न करें ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि चालान में वैध 10 अंकों के चरित्र में पैन / टैन है।

22 दिनांक 1-1-2005 से चालान पर स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना

{आरबीआई/2004/300 - (डीजीबीए).जीएडी.दिनांक 14 दिसंबर, 2004 और भारतीय रिज़र्व बैंक/2005/265 - (डीजीबीए) दिनांक 2532-65/42.01.034/2004-05.जीएडी.सं.एच-8824/42.01.034/2005-06) दिनांक 28 दिसम्बर, 2005}

करदाताओं को सही और शीघ्र ऋण सुनिश्चित करने की दृष्टि से केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी), भारत सरकार ने **1 जनवरी, 2005** से चालानों पर पैन/टैन का उल्लेख अनिवार्य करने के प्रावधानों को लागू करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, जब तक कि करदाताओं के पैन को चालान आईटीएनएस 280 और 282 या चालान आईटीएनएस 281 पर कटौतीकर्ता के टैन पर उद्धृत नहीं किया जाता है, जैसा भी मामला हो, बैंक शाखाओं द्वारा करों का कोई भुगतान स्वीकार नहीं किया जाएगा,। शाखाएं एक नोटिस को प्रमुखता से प्रदर्शित कर सकती हैं जिसमें कहा गया हो कि **1/1/2005 से** शाखाओं में **चालान पर पैन**/टैन की **अधिसूचना अनिवार्य है** और उस तारीख से पैन/टैन के बिना चालान स्वीकार नहीं करना है। पैन/टैन प्राप्त करने की प्रक्रिया आयकर विभाग

(http://www.incometaxindia.gov.in या http://www.tin-nsdl.com) की वेबसाइट पर उपलब्ध है। शाखाएं करदाताओं को कर जमा करने से पहले पैन/टैन प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन कर सकती हैं। पूर्व-मुद्रित पैन /टैन नंबर के साथ चालान फॉर्म नंबर 280 और 281 को लोड करने की सुविधा को भी आपकी नामित शाखाओं के माध्यम से व्यापक प्रचार दिया जा सकता है।

23 ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - डेटा गुणवत्ता में सुधार

{डीजीबीए.जीएडी.दिनांक 9 अक्तूबर, 2007 को दिनांक 3774/42.01.034/2007-08, भारतीय रिज़र्व बैंक/2007/206 (डीजीबीए).जीएडी.सं.6212/42.01.034/2007-08) दिनांक 6 दिसम्बर, 2007}

23.1 टिन पर अपलोड किए गए चालान विवरण में विसंगतियां

बैंकों के ध्यान में लाया गया था कि उनके द्वारा टिन पर अपलोड किए गए ओएलटीएएस डेटा टीडीएस/टीसीएस रिटर्न के माध्यम से प्रस्तुत सापेक्ष डेटा से मेल नहीं खाते हैं। पाई गई सामान्य अनियमितताएं निम्नवत है:

(i) ओएलटीएएस के माध्यम से अपलोड किए गए डेटा में भुगतान की तारीख को चालान जमा तिथि के रूप में डिजिटाइज किया गया है।

(ii) चालान क्रमांक, प्रमुख शीर्ष, पैन/टैन आदि गलत ढ़ंग से अपलोड करना।

(iii) चालान क्रमांक की मुहर चालान काउंटरफॉइल पर नहीं लगाई गई।

(iv) एकल चालान के विरूद्ध इंगित राशि को दो राशियों में विभाजित किया गया है और दो चालानों में रिपोर्ट किया गया है।

बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे उपरोक्त त्रुटियों से बचें और ओएलटीएएस डेटा को कैप्चर और अपलोड करते समय अधिक सावधान रहें।

23.2 डेटा गुणवत्ता की चिंता

पैन और सीआईएन को टिन को रिपोर्ट करने में सटीकता प्राप्त करने के लिए एजेंसी बैंकों को सलाह दी गई थी:

23.2.1 टिन-एनएसडीएल साइट से थोक पैन सत्यापन सुविधा का उपयोग करें;

23.2.2 जब भी आवश्यक हो पैन के प्रमाण पर जोर दें और

23.2.3 सुनिश्चित करें कि ग्राहक को दिया गया सीआईएन ओएलटीएएस पर अपलोड किया गया है। विशेष रूप से प्रस्तुति की तारीख के संदर्भ में सावधानी बरती जानी चाहिए।

24 कम्प्यूटरीकृत प्राप्तियों की शुरूआत और डेटा गुणवत्ता में सुधार

{आरबीआई/2008/328 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच.12070/42.01.034/2007-08) दिनांक 22 मई, 2008}

एजेंसी बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे ओएलटीएएस लेनदेनों के चालान भुगतान के लिए कम्प्यूटरीकृत रसीदें जारी करें, जिसमें निर्धारित प्रोफार्मा के अनुसार संगत आंकड़े शामिल हों।

अनुलग्नक A-IV-I और II दिनांक 01 जून, 2008 के अनुसार एजेंसी बैंकों को आगे निम्नानुसार अतिरिक्त दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई:

i) **डाटा प्रविष्टि की मेकर चेकर व्यवस्था:** मेकर चेकर सिस्टम में मेकर द्वारा की डेटा एंट्री को, गलत डेटा एंट्री की संभावना को कम करने के लिए को दूसरे चेकर द्वारा चेक किया जाता है।इसका सख्ती से पालन किया जाए।

ii) **सॉफ्टवेयर अलर्ट:** डेटा एंट्री त्रुटि को कम करने के लिए, संग्रहणी शाखाओं में डेटा एंट्री सॉफ्टवेयर को चेतावनी संदेश प्रदान करना चाहिए जहां पैन / टीएएन दर्ज नहीं किया गया है या संरचनात्मक रूप से अमान्य डेटा दर्ज किया गया है या पैन को टैन के लिए बने कॉलम में दर्ज किया गया है या जहां के बीच बेमेल है नाबालिग प्रमुख और मूल्यांकन वर्ष आदि।

iii) **सॉफ्टवेयर सत्यापन:** आप यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए सॉफ़्टवेयर सत्यापन आपके सिस्टम में शामिल किए गए हैं।

iv) **बैंक स्तर पर गुणवत्ता आश्वासन:** सभी एजेंसी बैंकों से सरकारी कर के संग्रह के संबंध में गुणवत्ता आश्वासन की उम्मीद की जाती है।

v) **अस्वीकृत फ़ाइल का पुन: अपलोड:** एनएसडीएल में डेटा फ़ाइल की अस्वीकृति को समाप्त करने के लिए टिन पर अपलोड करने से पहले ओएलटीएएस डेटा फ़ाइल को फ़ाइल सत्यापन यूटिलिटी (एफवीयू) के माध्यम से मान्य किया जा सकता है।

25 सरकारी राजस्व से संबंधित ई-भुगतान लेनदेन के लिए समय में कटौती

{आरबीआई/2008/275 (डीजीबीए).जीएडी.सं.10577/42.01.038/2007-08) दिनांक 3 अप्रैल, 2008}

सीबीडीटी राजस्व के ई-भुगतान के लिए अधिकृत बैंकों को सलाह दी गई थी कि ओएलटीएएस के तहत रात 8.00 बजे तक प्राप्त भुगतान को उसी दिन प्राप्त माना जा सकता है और उसके बाद प्राप्त भुगतान को अगले कार्य दिवस पर प्राप्त माना जा सकता है।

26 करदाताओं की कुछ श्रेणियों द्वारा कर का अनिवार्य इलेक्ट्रॉनिक भुगतान 1 अप्रैल, 2008 से

{RBI/2008/280 (DGBA) जीएडी.सं.10875/42.01.038/2007-08 दिनांक 10 अप्रैल, 2008}

सीबीडीटी ने निम्नलिखित श्रेणियों की करदाताओं के लिए करों का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान अनिवार्य कर दिया है:

a. एक कंपनी

b. एक व्यक्ति (एक कंपनी के अलावा) जिस पर धारा 44एबी के प्रावधान लागू होते हैं

इसलिए, बैंकों को सलाह दी गई थी कि वे अपनी शाखाओं को निर्देश दें:

i) नाम से कॉर्पोरेट करदाताओं की स्थिति की पहचान करना। सभी कॉर्पोरेट कंपनियों के पैन का चौथा अंक "सी" होगा। इसलिए ऐसे निरीक्षकों के भौतिक चालान को काउंटर पर स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए।

ii) करदाताओं से बैंक काउंटरों पर भौतिक चालान स्वीकार करना। आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत ई-भुगतान करने की जिम्मेदारी मुख्य रूप से करदाताओं की है।

iii) स्क्रीन पर ई-भुगतान के लिए तुरंत पावती उपलब्ध कराना।

iv) यह सुनिश्चित करने के लिए कि ई-भुगतान की लेनदेन आईडी बैंक की विवरणी में परिलक्षित होती है।

v) यदि करदाता को भुगतान करने, ई-भुगतान लेनदेन को पूरा करने, काउंटरफॉइल उत्पन्न करने आदि में किसी भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो अपने ई-भुगतान गेटवे पेज पर संपर्क अधिकारी प्रदर्शित करने के लिए, तो से संपर्क किया जाना चाहिए।

vi) आईटीडी या करदाताओं के सामने आने वाली किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए संपर्क विवरणों के साथ आईटीडी और एनएसडीएल को संपर्क अधिकारियों की सूची उपलब्ध कराना है, जिनसे आवश्यकता पड़ने पर संपर्क किया जा सकता है।

{आरबीआई/2008/321 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच.11895/42.01.038/2007-08) दिनांक 15 मई, 2008}

एजेंसी बैंकों को वित्तीय वर्ष 2007-08 के लिए आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आने वाले करदाताओं के नामों और क्षेत्रवार पैन और नामों वाली एक सीडी प्रदान की गई थी और आयकर अधिनियम की धारा 44एबी के तहत प्रावरित करदाताओं द्वारा चेक के साथ चालान जमा करने के मामले में निम्नलिखित कार्रवाई करने की सलाह दी गई थी, जिसे क्षेत्रवार पैन और धारा 44एबी के तहत आने वाले करदाताओं के नाम वाली सीडी से सत्यापित किया जा सकता है:

i) करदाता से अनुरोध है कि वह ई-भुगतान माध्यम से भुगतान करें।

ii) यदि वह ऐसा करने में असमर्थता का दावा करता है, तो चेक को इस चेतावनी के साथ स्वीकार करें कि इसे अगले भुगतान के लिए स्वीकार नहीं किया जाएगा और वह अधिनियम के तहत कार्यवाही के लिए उत्तरदायी हो सकता है।

iii) शाखा में नेट बैंकिंग खाता खोलने के लिए करदाता की मदद करें।

iv) करदाताओं की जानकारी के लिए ई-भुगतान करने के लिए बैंकों को एक संक्षिप्त लेख और पालन किए जाने वाले कदम (अनुबंध IV के अनुसार) भी प्रदान किए गए थे।

27 सरकारी लेन-देनों के ई-भुगतान के प्रेषण की अनुमेय अवधि – निजी क्षेत्र के बैंक और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक

{डीजीबीए.जीएडी.दिनांक 18 जुलाई, 2008 और भारतीय रिज़र्व बैंक/2010-11/229 (डीजी बीए) दिनांक 551/42.01.011/2008-09.जीएडी.सं.एच.2444/42.01.011/2010-11) दिनांक 8 अक्टूबर, 2010}

ई-भुगतानों के माध्यम से प्राप्त ईएएसआईईएसटी और ओएलटीएएस सहित सभी सरकारी लेनदेनों के लिए निजी क्षेत्र के बैंकों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के संबंध में प्रेषण अवधि क्रमश 1 अगस्त, 2008 और 1 नवंबर, 2010 से टी +1 कार्य दिवस (तिथि सहित) है।

28 सरकारी खातों में सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ब्याज की वसूली

{आरबीआई/2009/463 (डीजीबीए).जीएडी सं.H-9284/42.01.011/2008-09) दिनांक 28 अप्रैल, 2009}

(i) 1-5-2005 से 31-12-2006 की अवधि के दौरान प्रभावित लेन-देनों (राजस्व प्राप्तियों से संबंधित) के उन मामलों के लिए जिनमें दंडात्मक ब्याज पहले ही भुगतान किया जा चुका है, इनके लिए पुट थ्रू दिनांक निकालने की प्रयोज्यता:

मौजूदा अनुदेशों के अनुसार, सरकारी राजस्व के विप्रेषण के लिए विलंबित अवधि ब्याज की गणना के लिए निर्धारित विप्रेषण मानदंडों से 'पुट थ्रू डेट' को बाहर रखा गया था और ये अनुदेश विलंबित अवधि के ब्याज मामलों में लागू किए गए थे जहां बैंकों ने ब्याज का भुगतान नहीं किया था। महालेखा नियंत्रक द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि सरकारी प्राप्तियों के विप्रेषण के लिए परिकलित समयावधि से 'पुट थ्रू डेट' के बहिष्करण का लाभ उन बैंकों को भी दिया जाए जिन्होंने भुगतान करते समय विद्यमान अनुदेशों पर 1-05-2005 से 31-12-2006 की अवधि के दौरान दण्डात्मक ब्याज का भुगतान किया था। बैंकों द्वारा भुगतान किए गए दंडात्मक ब्याज के अतिरिक्त भुगतान को उनके विरूद्ध विलंबित अवधि के दंडात्मक ब्याज के, बाद के दावों के, साथ समायोजित किया जाएगा।

(ii) उत्पाद शुल्क और सेवा कर में इलेक्ट्रॉनिक लेखा प्रणाली के तहत बाहरी लेन-देन के लिए सरकारी खाते में सरकारी राजस्व के प्रेषण की अनुमेय अवधि (ईएएसआईईएसटी)

यह निर्णय लिया गया है कि बाहरी लेनदेन के लिए अधिकतम टी + 5 कार्य दिवसों (तिथि को छोड़कर) की अनुमति दी जाएगी। यह व्यवस्था ई-भुगतान (इंटरनेट के माध्यम से किए गए भुगतान) पर लागू नहीं होगी, जिसके लिए 18 जुलाई, 2008 के हमारे परिपत्र संख्या 2008-09/97 द्वारा अलग-अलग अनुदेश जारी किए गए हैं।

(iii) सरकारी प्राप्तियों के विलंबित विप्रेषण के लिए छोटी राशि की दंडात्मक ब्याज लगाना:

यह निर्णय लिया गया है कि 500/- रुपये अथवा उससे कम की राशि वाले विलंबित अवधि दंडात्मक ब्याज के छोटे-मोटे दावों को नजरअंदाज किया जाएगा और 1 जनवरी, 2008 से दंडात्मक ब्याज के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

(iv) ओएलटीएएस की प्रारंभिक अवधि के दौरान शाखाओं द्वारा अनुभव की जाने वाली शुरुआती समस्याओं के कारण दंडात्मक ब्याज की छूट:

प्रणाली में स्थिरता आने से पहले ओएलटीएएस के कार्यान्वयन की प्रारंभिक अवधि के दौरान उत्पन्न विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, यह निर्णय लिया गया है कि छः तिमाहियों (अर्थात 1/04/2005 से 30/09/2006) को दंडात्मक ब्याज के दायरे से छूट दी जाए।

इसके अलावा, ये अनुदेश पीपीएफ/एससीएसएस आदि जैसे वित्त मंत्रालय की जमा योजनाओं के तहत निधियों के विप्रेषण पर लागू नहीं होंगे।

29 दूरस्थ इलाकों, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकारी राजस्व को सरकारी खाते में भेजने की अनुमेय अवधि

{आरबीआई/2009-10/381 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच.7790/42.01.011/2009-10) दिनांक 6 अप्रैल, 2010}

यह निर्णय लिया गया है कि जम्मू और कश्मीर, लेह, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, पूर्वोत्तर क्षेत्र (अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा), झारखंड और छत्तीसगढ़ में स्थित शाखाओं के संबंध में सरकारी प्राप्तियों को सीएएस, आरबीआई, नागपुर को मानवीय रूप से विप्रेषित करने के लिए दिनांक 01-01-2010 से टी+12 कार्य दिवसों की अवधि (तिथि को छोड़कर, जहां टी वह दिन है जब शाखा को धन उपलब्ध होता है) की अनुमति दी जाती है।

दूरस्थ, कठिन और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए उपर्युक्त मानदंड पीपीएफ / एससीएसएस आदि जैसे वित्त मंत्रालय की जमा योजनाओं के तहत धन के विप्रेषण पर लागू नहीं होंगे।

30 डेबिट / क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी खाते में विप्रेषण के लिए अनुमेय अवधि

{आरबीआई/2014-15/416 (डीजीबीए).जीएडी.सं.एच-3203/42.01.011/2014-15) दिनांक 21 जनवरी, 2015)}

डेबिट / क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी राजस्व के भुगतान के लिए एजेंसी बैंकों को निम्नलिखित अतिरिक्त मानदंडों का पालन करना आवश्यक है:

a) टी + 1 कार्य दिवस के प्रेषण मानदंडों, जिसमें पुट थ्रू डेट भी शामिल है, का सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, जहां "टी" वह दिन है जब प्राप्तकर्ता बैंक शाखा के पास पैसा उपलब्ध होता है।

b) ई-रसीद को सरकारी खाते में देरी से, यदि कोई हो, भेजे जाने पर दंडात्मक ब्याज लगाया जाएगा, अर्थात टी+1 कार्य दिवस से अधिक की देरी पर, और

c) सभी निपटान, भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में निहित प्रावधानों और उसके तहत बनाए गए नियमों और विनियमों के अनुरूप होना चाहिए।

****

अनुबंध।

ऑन-लाइन कर लेखाकन प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखांकन प्रक्रिया

---

1. प्राप्तकर्ता शाखाओं में करों की स्वीकृति की प्रक्रिया

1.1 करदाता अधिकृत बैंक की किसी भी अधिकृत शाखा में प्रत्यक्ष कर का भुगतान नकद, खाते में प्रत्यक्ष डेबिट या उसी बैंक या उसी केंद्र, जहां भुगतान किया जाता है, स्थित किसी अन्य बैंक/शाखा में आहरित ड्राफ्ट /चेक द्वारा कर का भुगतान कर सकता है। बाहरी चेक/ड्राफ्ट द्वारा कर का भुगतान किसी अधिकृत बैंक में या प्राधिकृत बैंक/शाखा को के इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से विप्रेषण भी किया जा सकता है। प्रत्येक भुगतान के लिए निर्धारित प्रारूप में चालान होना चाहिए। चालान प्रारूप एक एकल प्रतिलिपि चालान है जिसमें मुख्य चालान शीर्ष पर है और निचले भाग में करदाता का काउंटरफॉइल चालान के है (नमूना अनुबंध 'ए' पर उपलब्ध है)।

1.2 प्राप्तकर्ता बैंक की शाखा के काउंटर पर

प्राप्तकर्ता शाखा के प्राप्त करने वाले क्लर्क/टेलर को भुगतान स्वीकार करते समय निम्नलिखित बिंदुओं की जांच करनी होगी: –

a. क्या चालान का मुख्य हिस्सा और करदाता के काउंटरफॉइल फॉर्म को ठीक से भरा गया है और राशि एवं खाते के मुख्य शीर्ष, जिस में राशि का हिसाब/जमा किया जाना है, उसे सही ढंग से दर्ज किया गया है;

b. क्या स्थायी एगणना संख्या (पैन) या कर कटौती खाता संख्या (टैन), करदाता का नाम और पता, आकलन वर्ष और भुगतान की प्रकृति और प्रकार का विवरण ठीक से भरा गया है। राशि, शब्दों और आंकड़ों, दोनों में सही ढंग से लिखी जानी चाहिए।

c. क्या निर्धारित स्थान पर चालान में स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) दर्ज किया गया है। आयकर अधिनियम की धारा 139 ए (5) (बी) के तहत पैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। इसी प्रकार, अधिनियम की धारा 203ए के अंतर्गत टैन का उल्लेख करना अनिवार्य है। करदाता द्वारा उद्धृत इस संख्या को मान्य किया जाना चाहिए (यह देखने के लिए जांच की जानी चाहिए कि क्या यह वैध पैन / टैन संरचना के अनुरूप है) और कर भुगतान स्वीकार करने वाले नामित बैंकों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भुगतान के लिए चालान केवल तभी स्वीकार किए जाते हैं जब चालान में एक वैध पैन उद्धृत किया जाता है। हालांकि, जहां करदाता इंगित करता है कि उसने पहले ही पैन या टैन के आवंटन के लिए आवेदन किया है, लेकिन अभी तक इसे आवंटित नहीं किया गया है, तो बैंक द्वारा कर भुगतान चालान स्वीकार किए जा सकते हैं बशर्ते करदाता चालान में पैन / टैन आवेदन संख्या इंगित करता है। ऐसे मामलों में, यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि **चालान में करदाता के पूरे पते का उल्लेख किया** गया है।

1.3 चालान की जांच करने और खुद को संतुष्ट करने के बाद कि नकद, चेक या ड्राफ्ट की राशि चालान में दिखाई गई राशि से सहमत है, और यह भी कि चेक पोस्ट डेटेड / पुराना नहीं है, शाखा के रिसीविंग टेलर या काउंटर-क्लर्क जमाकर्ता को एक पेपर टोकन जारी करेंगे ताकि उसे काउंटरफॉइल रसीद की डिलीवरी की सुविधा मिल सके। अन्य बैंक शाखाओं में चेक या ड्राफ्ट के साथ जमा किए गए चालान के मामले में, काउंटरफॉइल रसीद केवल चेक या ड्राफ्ट की राशि की वसूली पर जारी की जाएगी और इसलिए पेपर टोकन पर वह तारीख होनी चाहिए जिस पर वह उपलब्ध होगा।

1.3.1 नकद के साथ प्रस्तुत किए गए चालान

जांच के बाद यदि नकद के साथ चालान दिया जाता है, तो उस पर 'नकद प्राप्त' लिखा होगा। बैंक चालान के मुख्य हिस्से और करदाता के काउंटरफॉइल दोनों पर बैंक और शाखा के नाम, शाखा का बीएसआर कोड (7 अंक), राशि जमा करने की तारीख (डीडीएमएमवाईवाई) और चालान का विशिष्ट क्रमांक (5 अंक) का उल्लेख करने वाले एक मुहर लगाएगा। मुहर मुख्य भाग के साथ-साथ चालान के करदाता के काउंटरफॉइल दोनों पर प्रभावित होगा। यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती जानी चाहिए कि रसीद पर मुहर की निशानी स्पष्ट और सुस्पष्ट है।

शाखा का एक अधिकृत अधिकारी करदाता के काउंटरफॉइल पर पूर्ण हस्ताक्षर करेगा और राशि प्राप्ति की पुष्टि स्वरूप चालान की मुख्य प्रति पर आद्याक्षर करेगा। करदाता के काउंटरफॉइल में, प्राप्त राशि को शब्दों और आंकड़ों दोनों में इंगित किया जाएगा। प्राप्त करदाता का काउंटरफॉइल जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा और उसके बाद मुख्य प्रति रसीद स्क्रॉल में स्क्रॉल करने के लिए पारित की जाएगी।

1.3.2 चेक/ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालान

चेक/ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत किए गए चालान पर 'डबल डेट मुहर ' लगाई जाएगी ताकि लिखत की जमा की तारीख के साथ-साथ उसकी प्राप्ति की तारीख भी दर्शाई जा सके। यह संभव हो सकता है कि कुछ शाखाएं काउंटर पर चालान जमा होते ही चालान की ब्रांडिंग की परंपरा का पालन कर रही हों। उस स्थिति में डबल डेट मुहर आवश्यक नहीं हो सकता है। हालांकि, चालान की मुख्य प्रति और करदाता के काउंटरफॉइल दोनों पर आवक तिथि मुहर लगाया जाना हमेशा सुनिश्चित किया जाए।

जाँचकर्ता अधिकारी शुरू में यह सुनिश्चित करेगा कि चेक/ड्राफ्ट की राशि और जमाकर्ता द्वारा चालान में दर्ज राशि में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद चेक/ड्राफ्ट को भुगतान के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद, चेक/ड्राफ्ट की **भुगतान पर, डबल डेट स्टैम्प पर भुगतान की तारीख या** चालान **में एसपीई में** इंगित **की जाएगी, जैसा भी मामला हो।** बैंक एक कॉपी चालान के मुख्य और करदाता दोनों के काउंटरफॉइल पर बैंक और शाखा के नाम, शाखा के बीएसआर कोड (7 अंक) राशि की जमा तिथि (डीडीएमएमवाईवाई) और चालान के अद्वितीय सीरियल नंबर (5 अंक) का उल्लेख करने वाले एक स्टाम्प के साथ मुहर लगाएगा। राशि प्राप्त करने पर, चालान पर हस्ताक्षर करके, करदाता का काउंटरफॉइल टोकन के आत्मसमर्पण के विरूद्ध जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा।

1.3.3 चालानों पर क्रमांक लगाना

प्रत्येक दिन के लिए सभी चालान (नकद और चेक द्वारा भुगतान दोनों) के लिए क्रमवार नंबर दिया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी विशेष दिन जारी किए गए प्रत्येक चालान पर लगाई गई क्रमांक बाद में इसका पता लगाने के लिए **अद्वितीय** होना चाहिए। इसलिए **बैंक को यह सुनिश्चित** करना चाहिए कि नकद **के साथ जमा किए गए चालानों को दिए गए क्रमांक, उन चालानों को दिए गए सीरियल नंबरों के साथ ओवरलैप न हों, जिनके विरूद्ध उस दिन चेक प्राप्त किए गए हैं।**

उसी शाखा में देय नकद और चेक/ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालान, काउंटर पर विधिवत प्राप्त करके, चालान का काउंटरफॉइल जमाकर्ता को वापस कर दिया जाएगा। एक ही बैंक की अलग-अलग शाखा या उसी केंद्र पर स्थित किसी अन्य बैंक की चेक/ड्राफ्ट के साथ दिए गए चालान, करदाता के काउंटरफॉइल को किसी भी दिन के क्लियरिंग के अवैतनिक दस्तावेजों की वापसी के लिए 'लोकल बैंकर्स क्लियरिंग हाउस' के नियमों के तहत निर्धारित कार्य दिवस के बाद विधिवत प्राप्त नहीं किया जाएगा।

1.4.1 चेक/ड्राफ्ट के साथ प्रस्तुत चालान के मामले में, चालान के मुख्य भाग पर चेक भुगतान की तारीख पर भी मुहर लगाई जाएगी, जिसे रसीद स्क्रॉल के साथ क्षेत्रीय लेखा कार्यालय (जेडएओ) को आगे प्रेषित करने के लिए बैंक में रखा जाएगा। हालांकि आयकर अधिनियम के अनुसार चेक/डिमांड ड्राफ्ट प्रस्तुत करने की तारीख को कर के भुगतान की तारीख के रूप में माना जाएगा, लेकिन चेक/डिमांड ड्राफ्ट को वसूली के बाद ही स्क्रॉल किया जाएगा।

1.4.2 प्राप्ति चालान पर दोहरी तिथि

चालान का मुख्य भाग, जिसके माध्यम से चेक / ड्राफ्ट जमा किया जाता है, इसमें, निम्नानुसार दो तिथियां होंगी:

i) जमा की तिथि: DDMMYY (रबर स्टाम्प पावती में)

ii) प्राप्ति की तिथि: DDMMYY (चालान में इंगित स्थान पर)

नकद जमा के मामले में जमा की तिथि और प्राप्ति की तारीख समान होगी।

1.4.3 संग्रहणकर्ता बैंक किसी अन्य प्रारूप में रसीद जारी नहीं करेगा।

2. संग्रहणकर्ता शाखा द्वारा स्क्रॉल तैयार करना

2.1 प्रत्येक दिन बैंक शाखा काउंटर **पर** प्राप्त सभी चालानों को क्रमवार एक नंबर दिया जाएगा, जिसके विरूद्ध नकद भुगतान किया गया है या उस तारीख को चेक / ड्राफ्ट का भुगतान किया गया हैं।

2.2 बैंक काउंटर पर करदाता द्वारा चालान जमा किए जाने पर नाम और पैन, क्रमांक नंबर, जमा की तारीख और शाखा का बीएसआर कोड जैसे सभी चालान फ़ील्ड को कैप्चर करना आवश्यक है। चालान के क्षेत्रों की डेटा संरचना को कैप्चर किया जाना है और प्रेषित किया जाना है जैसा कि आयकर विभाग द्वारा बैंकों को सूचित किया जाएगा। करदाता का नाम और स्थायी खाता संख्या (पैन) हमेशा रसीद और भुगतान स्क्रॉल में शामिल किया जाएगा।

2.3 ग्राहको के लिए बैंकिंग कार्य समय के समाप्ति पर, बैंक शाखा को उन सभी चालानों की पहचान करनी चाहिए जिनके विरुद्ध दिन के लिए नकद में भुगतान प्राप्त किया गया है या जिनके लिए चेक / ड्राफ्ट द्वारा भुगतान दिन के लिए प्राप्त किया गया है। चूंकि इन सभी चालानों का विवरण पहले से ही बैंक के कंप्यूटर सिस्टम में है, इसलिए शाखा को उस दिन के लिए भुगतान किए गए सभी चालान डेटा वाली एक फाइल तैयार करनी चाहिए और बैंकों के लिंक सेल के माध्यम से आयकर विभाग के टिन को आगे प्रसारण के लिए इसे अपनी नोडल शाखा को प्रेषित करना चाहिए। तथापि, गैर-कम्प्यूटरीकृत/गैर-नेटवर्ककृत प्राधिकृत शाखाओं को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उसकी निकटतम कम्प्यूटरीकृत/नेटवर्क शाखा से डाटा नोडल शाखा को प्रेषित किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि उस दिन जिस चालान का भुगतान किया गया है, उसे छोड़ा न जाए। एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के माध्यम से विस्तारित एक रनिंग स्क्रॉल सीरियल नंबर प्रत्येक प्रकार के कर (प्रमुख प्रमुख) से संबंधित रिकॉर्ड को दिया जाएगा जो किसी विशेष दिन प्रेषित किए जाते हैं। रिकॉर्ड की पूरी डेटा संरचना और फाइल जो बैंक द्वारा विभाग को प्रेषित की जानी है, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में होगी। आयकर विभाग को प्रेषित किए जाने के बाद संग्रह शाखा किसी भी मामले में ऑनलाइन डेटा फ़ाइल को अपने अंत में नहीं बदलेगी।

2.4 क्लियरिंग रिटर्न का प्रतिपादन

संग्रहणकर्ता शाखा को उन सभी चालानों की भी पहचान करनी चाहिए जिनके साथ प्रस्तुत लिखतों को बिना भुगतान किए वापस कर दिए थे। संबंधित चालान के साथ ऐसे लिखतों को बैंक में अलग से रखा जाना चाहिए ताकि उचित समझे जाने पर आगे आवश्यक कार्रवाई की जा सके।

2.5 संग्रहणकर्ता शाखा दैनिक आधार पर अपने कंप्यूटर में उपलब्ध चालान डेटा से कर के प्रकार (प्रमुख शीर्ष-वार) के आधार पर जो आयकर विभाग को प्रेषित किया गया है, फॉर्म में .....स्क्रॉल के और फॉर्म में सारांश के अलग-अलग प्रिंटआउट भी निकलेगी। एक वित्तीय वर्ष (1 अप्रैल से 31 मार्च) के माध्यम से विस्तारित वही चल रहा सीरियल नंबर, जो संबंधित दिन के लिए प्रेषित स्क्रॉल को दिया गया था, संबंधित कर के प्रकार (प्रमुख प्रमुख) के उपयुक्त संक्षिप्त नाम द्वारा पूर्वनिर्धारित, स्क्रॉल पर मुद्रित किया जाएगा। संग्रह शाखा किसी भी मामले में डेटा से कोई मुद्रित स्क्रॉल या सारांश उत्पन्न नहीं करेगी जो पहले विभाग को प्रेषित डेटा से किसी भी तरह से बदल जाती है। इस प्रकार शाखा द्वारा उत्पन्न स्क्रॉल, बैंक द्वारा विभाग के टिन को ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित डेटा से आरसीसी द्वारा उत्पन्न स्क्रॉल से बिल्कुल मेल खाएंगे। इसके बाद, शाखा कंप्यूटर मुद्रित सारांश और रसीद स्क्रॉल का एक सेट तैयार करेगी और प्रत्येक स्क्रॉल के साथ उसी सीरियल क्रम में व्यवस्थित भौतिक चालान संलग्न करेगी जिसमें उन्हें स्क्रॉल में दर्ज किया जाता है। अगले कार्य दिवस की शुरुआत में, प्राप्तकर्ता शाखा इसे जेडएओ को आगे के प्रसारण के लिए नोडल शाखा को अग्रेषित करेगी।

2.6 त्रुटि का संचरण

करदाता या भुगतान की गई राशि या भुगतान के मुख्य शीर्ष की रिपोर्ट करने में एकत्रित बैंक शाखा द्वारा किसी भी त्रुटि के मामले में, बैंक एक त्रुटि रिकॉर्ड के माध्यम से, आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में, टिन को सही जानकारी ऑनलाइन माध्यम से प्रेषित करेगा। राशि और खाते के शीर्ष में त्रुटियों के सुधार की सूचना भी 'एरर स्क्रॉल' के माध्यम से जेडएओ को दी जाएगी, जिसे नोडल शाखा को भेजा जाएगा। बैंक द्वारा टिन को दी गई कर भुगतान की राशि ही आयकर विभाग द्वारा करदाता द्वारा किए गए भुगतान के रूप में स्वीकार की जाएगी।

3. आयकर धन वापसी आदेश (आईटीआरओ)/ईसीएस के भुगतान की प्रक्रिया

3.1 प्रत्यक्ष कर की धन वापसी का कार्य, एक आईटीडी केंद्र / एक जिले के, किसी अधिकृत बैंक की केवल एक शाखा को सौंपा जाता है, जिसमें आम तौर पर भारतीय रिज़र्व बैंक, भारतीय स्टेट बैंक या उसके सहयोगी बैंक होते हैं। करदाता द्वारा धन वापसी आदेश को अपने अंतरण के लिए उसी शाखा में प्रस्तुत किया जाएगा जिसमें उसका खाता अनुरक्षित है। वैकल्पिक रूप से, इसे समाशोधन के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। धन वापसी आदेश लेने के लिए अधिकृत आयकर विभाग के अधिकारियों के नमूना हस्ताक्षर आयकर अधिकारियों द्वारा संबंधित भुगतान करने वाली शाखाओं को अग्रिम रूप से भेजे जाएंगे। नमूना हस्ताक्षर आयकर विभाग के एक अधिकारी द्वारा विधिवत प्रमाणित किया जाएगा, जिसका नमूना हस्ताक्षर पहले से ही शाखा के साथ रिकॉर्ड पर है। अधिकृत अधिकारी में किसी भी बदलाव की सलाह संबंधित शाखा को तत्काल दी जाएगी। कार्यमुक्त अधिकारी कार्यमुक्त अधिकारी के नमूना हस्ताक्षर को प्रमाणित करेगा। महालेखा नियंत्रक द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, भुगतान के लिए धन वापसी आदेश पारित करते समय, पासिंग अधिकारी को नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स के भुगतान के संबंध में बैंकों द्वारा आमतौर पर बरती जाने वाली सावधानियों के अलावा अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। भुगतानकर्ता को आयकर धन वापसी आदेश (आईटीआरओ) के पिछले भाग में 'दावेदारों के हस्ताक्षर' के लिए प्रदान की गई जगह में अपना हस्ताक्षर करना आवश्यक है। रिफंड सूचना से संबंधित प्रक्रिया वर्तमान में जारी रहेगी, सिवाय इसके कि भुगतान किए गए आईटीआरओ और मुद्रित भुगतान स्क्रॉल की सलाह अब बैंक द्वारा आयकर विभाग को नहीं भेजी जाएगी।

3.2 प्राप्तियों के मामले में, धन वापसी को भुगतान करने वाली शाखा द्वारा कर के प्रकार के अनुसार वर्गीकरण करना आवश्यक है जिसके तहत धन वापसी किया जाता है। आईटीआरओ के भुगतान के संबंध में अलग से प्रमुख शीर्षवार भुगतान रिकॉर्ड बनाए जाएंगे।

3.3 प्रत्यक्ष कर रिफंड को आरबीआई की इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन योजना (ईसीएस) के माध्यम से सीधे करदाता के बैंक खाते में जमा किया जा सकता है। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए, करदाता अपने आय विवरणी में अपने बैंक खाते (बचत या चालू), खाता संख्या और बैंक शाखा कोड (9 अंक) के प्रकार का उल्लेख करके एक जनादेश देता है। करदाता के रिटर्न को लागू करने और आकलन अधिकारी द्वारा रिफंड के निर्धारण के बाद, आरसीसी के अधिकार क्षेत्र में सभी करदाता रिफंड (जिसमें ईसीएस के माध्यम से क्रेडिट मांगा गया है) स्वचालित रूप से आरसीसी में कंप्यूटर सिस्टम पर समेकित हो जाते हैं। यह सभी धनवापसी डेटा डाउनलोड, एन्क्रिप्ट किया जाता है और चुंबकीय मीडिया (फ्लॉपी या पुनर्लेखन योग्य सीडी) पर कॉपी किया जाता है या इलेक्ट्रॉनिक रूप से प्रेषित किया जाता है। यह आरसीसी द्वारा स्थानीय जेडएओ के साथ-साथ आरबीआई या एसबीआई की रिफंड जारी

करने वाली शाखा को भेजा जाता है। फाइल में डेटा को सत्यापित करने के बाद, बैंक रिफंड की कुल राशि के लिए आयकर विभाग के खाते को डेबिट करता है और उसके बाद बैंकों की विभिन्न स्थानीय शाखाओं को समाशोधन के माध्यम से निर्देश जारी करता है, जहां करदाता के खाते स्थित हैं। विभाग के खाते में यह एकल डेबिट उस दिन के लिए बैंक द्वारा आयकर विभाग को प्रेषित भुगतान (रिफंड) डेटा में दिखाई देता है। यदि खाता बंद होने आदि जैसे कारणों से करदाता के खातों में इनमें से कोई भी क्रेडिट प्रभावी नहीं होता है, तो बाद में आयकर विभाग के खाते में ईसीएस रिटर्न के लिए एक अलग माइनस डेबिट प्रविष्टि द्वारा इसका हिसाब लगाया जाता है और उस विशेष दिन के लिए प्रेषित भुगतान (रिफंड) डेटा के माध्यम से आयकर विभाग को सूचित किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया (फ्लॉपी या पुनर्लेखन योग्य सीडी आदि) में फाइलें कंप्यूटर मुद्रित भुगतान (रिफंड) स्क्रॉल के साथ जेडएओ को लौटा दी जाती हैं, जबकि वही डेटा बैंक द्वारा आयकर विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) के माध्यम से आयकर विभाग को ऑनलाइन प्रेषित किया जाता है।

4. भुगतान (धनवापसी) की स्क्रॉल तैयार करना

4.1 भुगतान स्क्रॉल तैयार करने की प्रक्रिया रसीद स्क्रॉल के लिए लागू प्रक्रिया के समान होगी।

4.2 स्क्रॉल को रसीदों से संबंधित सेट के समान सेट में बनाया जाएगा, सिवाय इसके कि चालान के बजाय, भुगतान किए गए रिफंड ऑर्डर स्क्रॉल के साथ होंगे। भुगतान किए गए रिफंड वाउचर के बारे में पूरा डेटा भुगतान करने वाले बैंक द्वारा लिंक सेल को इलेक्ट्रॉनिक रूप से स्थानांतरित किया जाएगा ताकि विभाग के टिन को आगे प्रेषित किया जा सके। भुगतान किए गए धन वापसी आदेश के साथ भौतिक स्क्रॉल नोडल शाखा के माध्यम से जेडएओ को अग्रेषित किए जाएंगे। यदि नोडल शाखा स्थानीय रूप से स्थित नहीं है, तो उपरोक्त सभी दस्तावेज (रसीद / भुगतान स्क्रॉल आदि) हमेशा पंजीकृत डाक द्वारा भेजा जाना चाहिए।

4.3 ईसीएस धन वापसी के मामले में, डेटा लिंक सेल और बाद में आयकर विभाग को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा, जबकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वही ईसीएस विवरण नोडल शाखा के माध्यम से भुगतान बैंक द्वारा स्थानीय जेडएओ को भेजा जाएगा।

5. करदाता द्वारा काउंटरफॉइल का गुम हो जाना

जमाकर्ताओं द्वारा प्राप् त चालान काउंटरफॉइल गम हो जाने की स्थिति में, बैंक शाखाएं, करदाताओं से **जमा प्रमाण पत्र** जारी करने के लिए लिखित में एक विशिष्ट अनुरोध प्राप्त होने पर, जमाकर्ता को उनके रिकॉर्ड के आधार पर जारी कर सकती हैं। प्रत्येक मामले में आवेदक की प्रामाणिकता के बारे में खुद को संतुष्ट करना और अपने विवेक पर मामूली शुल्क ले सकता है। प्रमाण-पत्र में चालान विवरण अर्थात राशि, बैंक का नाम और शाखा, बीएसआर कोड और चेक / नकद जमा करने की तारीख, मुख्य शीर्ष, चालान क्रमांक, चेक भुगतान की तारीख / नकदी जमा करना और शाखा का संग्रह स्क्रॉल संख्या और तारीख जिस पर कर भुगतान का विवरण पहले प्रेषित किया गया है।

6. नोडल शाखा के कार्य

6.1 नोडल शाखा अपने अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी प्राप्त करने वाली शाखाओं (अपनी प्राप्तियों सहित) द्वारा प्रतिदिन रिपोर्ट किए गए संग्रह/रिफंड के त्वरित और सटीक प्रसारण, लेखांकन के लिए जिम्मेदार होगी। यह इससे जुड़ी सभी प्राप्त शाखाओं के संग्रह (अपने स्वयं के संग्रह सहित) को आरबीआई, सीएएस, नागपुर में सरकारी खाते में शीघ्र प्रेषण के लिए भी जिम्मेदार होगा। यह जेडएओ के साथ आंकड़ों के मिलान के लिए भी जिम्मेदार होगा।

6.2 संग्रहण शाखाओं से किसी विशेष दिन के लिए वसूल किए गए सभी चालानों के संबंध में ऑन-लाइन डेटा प्राप्त होने पर, नोडल शाखा दिन-प्रतिदिन के आधार पर निम्नलिखित कार्रवाई करेगी:

a. यह अपने कंप्यूटर सिस्टम पर चालान डेटा का मिलान करेगा और आयकर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में डेटा को अपने लिंक सेल में प्रेषित करेगा ताकि उसी दिन विभाग के टिन को आगे के प्रसारण के लिए उस दिन प्रसारित किए जा रहे सभी चालान रिकॉर्ड को एक सामान्य नोडल शाखा स्क्रॉल संख्या और तारीख दी जा सके।

b. यह फ्लॉपी या अन्य मीडिया (जैसा कि जेडएओ द्वारा सूचित किया गया है) में कंप्यूटर डेटा के आधार पर सारांश और मुख्य स्क्रॉल की एक प्रति भी उत्पन्न करेगा और इसे अगले कार्य दिवस पर जेडएओ को प्रेषित करेगा।

c. संग्रहणी शाखा से कंप्यूटर-जनित शाखा स्क्रॉल की हार्ड कॉपी प्राप्त होने पर, नोडल शाखा यह सत्यापित करेगी कि ये कंप्यूटर-जनित शाखा स्क्रॉल संग्रहणी शाखाओं द्वारा पहले प्रसारित डेटा से बिल्कुल मेल खाते हैं। यह सभी शाखाओं से प्राप्त इन कंप्यूटर मुद्रित शाखा स्क्रॉल (चालान के साथ) को मुख्य स्क्रॉल के साथ-साथ प्रमुख शीर्ष -वार सिलाई करके व्यवस्थित करेगा। यह प्रमुख शीर्ष-वार मुख्य स्क्रॉल और सारांश का एक कंप्यूटर प्रिंटआउट भी उत्पन्न करेगा। **इसके बाद यह इन्हें (चालान के साथ) दैनिक आधार पर संबंधित जेडएओ को भेजेगा।**

d. उपरोक्त (ग) में चर्चा के अनुसार चालान के बिना उसी तरीके से तैयार स्क्रॉल का दूसरा सेट नोडल शाखा द्वारा अपने रिकॉर्ड के लिए रखा जाएगा।

e. नोडल शाखा इसी तरह भुगतान (यानी धन वापसी) के लिए कंप्यूटर मुद्रित अलग मुख्य स्क्रॉल भी उत्पन्न करेगी, और उन्हें भुगतान किए गए आईटीआरओ के साथ जेडएओ को अग्रेषित करेगी। यह इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर ईसीएस धन वापसी विवरण स्थानीय जेडएओ को भी अग्रेषित करेगा। धन वापसी डेटा (पेपर आईटीआरओ और ईसीएस रिफंड के संबंध में) नोडल शाखा द्वारा लिंक सेल के माध्यम से टिन को ऑनलाइन प्रेषित किया जाएगा। यह भुगतान किए गए आईटीआरओ की सूचना / सूचनाओं को सहेजे रखेगा।

f. हर साल अप्रैल माहमें प्रथम 15 दिनों के दौरान, नोडल शाखाएं स्क्रॉल के दो अलग-अलग सेट प्रसारित और तैयार करेंगी - एक अप्रैल लेनदेन से संबंधित सामान्य स्क्रॉल और दूसरा मार्च लेनदेन से संबंधित (जिसका अर्थ है कि प्राप्तकर्ता शाखाओं को प्राप्त करके 31 मार्च तक जमा और मंजूर किए गए चेक / ड्राफ्ट / आईटीआरओ के स्क्रॉल और 31 मार्च के बाद लेकिन 15 अप्रैल से पहले नोडल शाखा को भेजे गए) - इन्हें नोडल शाखा द्वारा मार्च अवशिष्ट खाते के रूप में स्क्रॉल किया जाएगा। नोडल शाखाएं इन लेनदेन को मार्च लेनदेन के रूप में शामिल करने के लिए नागपुर में लिंक सेल को सूचित करेंगी। नोडल शाखाएं अप्रैल के लेनदेन के लिए एक और स्क्रॉल भेजेंगी, जिसमें खाते के महीने को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। 31 मार्च को या उसके बाद दिए गए किसी भी चेक/ड्राफ्ट को अप्रैल के लेनदेन के हिस्से के रूप में माना जाएगा। हालांकि, इस निर्देश के आलोक में कि उन सभी चालानों के लिए डेटा जिनके लिए भुगतान किसी दिए गए दिन आयकर विभाग को ऑनलाइन प्रेषित किया जाना चाहिए, केवल असाधारण मामलों में अलग मार्च अवशिष्ट स्क्रॉल की आवश्यकता होनी चाहिए।

g. नोडल शाखा अपने द्वारा लेखांकित समेकित राशि को दैनिक आधार पर अपने लिंक सेल को हस्तांतरित करेगी।

7. संग्रहीत कर को सरकारी खातों में जमा करना

7.1 नोडल शाखा अपने नियंत्रण में आने वाली सभी प्राप्तकर्ता शाखाओं के लिए एक पूलिंग केंद्र के रूप में कार्य करती है और यह जेडएओ को लेनदेन (सभी संबंधित दस्तावेजों यानी चालान और स्क्रॉल के साथ) की रिपोर्टिंग के लिए जिम्मेदार है। यह, आयकर विभाग को ऑनलाइन प्रेषणके लिए और साथ ही संग्रहीत राशि को भारतीय रिजर्व बैंक, केंद्रीय लेखा अनुभाग, नागपुर में जमा करने के लिए, इन सभी लेनदेन से संबधित चालान डेटा को नागपुर स्थित मअपने लिंक सेल को प्रेषित करने के लिए भी जिम्मेदार है।

7.2 नोडल शाखा एक दैनिक ज्ञापन तैयार करेगी और इसे दैनिक आधार पर नागपुर स्थित मअपने लिंक सेल (एसबीआई के मामले में जीएडी, मुंबई) को भेजेगी, जो बदले में आरबीआई, सीएएस, नागपुर के साथ दैनिक निपटान करेगी।

7.3 बैंकों को नागपुरमें स्थित लिंक सेल, विभाग के कर सूचना नेटवर्क (टिन) को प्रेषित करने के लिए, नोडल शाखा से प्राप्त चालान डेटा को समेकित करते हुए दैनिक प्राप्तियों की निगरानी भी करेगा और नोडल शाखाओं से

प्राप्त दैनिक ज्ञापनों की सटीकता की जांच करेगा। इसके पश्चात लिंक सेल दैनिक ज्ञापन सीएएस, आरबीआई, नागपुर को प्रेषित करेगा।

7.4 बैंकों की नोडल शाखाएं नागपुर में स्थित अपने लिंक सेल, के साथ जेडएओ के साथ द्वारा निपटाई गई राशि का, मासिक मिलान करेंगी। अपने रिकॉर्ड के आधार पर जेडएओ, नोडल शाखाओं से प्राप्त विवरणों को प्रमुख शीर्ष-वार और नोडल बैंक-वार सत्यापित करेंगे। किसी भी विसंगति के मामले में, नोडल शाखा तुरंत सुधार करेगी और जेडएओ को सूचित करते हुए नागपुर स्थित मअपने लिंक सेल के माध्यम से सीबीडीटी के खाते में पहले से जमा / डेबिट की गई राशि में अंतर को समायोजित करेगी।

7.5 जेडएओ और लिंक सेल के साथ लेनदेन के अंतिम मिलान के उद्देश्य से, सीएएस, आरबीआई, नागपुर एक मासिक विवरण तैयार करेगा और इसे जेडएओ और बैंकों के लिंक सेल को सूचित करेगा। भारतीय रिजर्व बैंक, सीएएस, नागपुर अगले महीने की 20 तारीख तक सीसीए, सीबीडीटी को प्रमुख शीर्ष-वार प्राप्तियों/रिफंड आदि को दर्शाते हुए एक मासिक विश्लेषण प्रस्तुत करेगा।

8. कर संग्रह के विप्रेषण की अवधि और दंडात्मक ब्याज लगाया जाना

8.1 प्राधिकृत बैंकों की नामित शाखाओं द्वारा किए गए कर संग्रहण को दैनिक आधार पर तुरंत सरकारी खाते में जमा किया जाना होता है। एजेंसी बैंकों द्वारा संग्रहीत कर को सीएएस, नागपुर के सरकारी बैंकों को भेजने के लिए अनुमत अधिकतम दिनों से संबधित जानकारी निम्नवत है

माध्यम	**सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए प्रेषण अवधि**		**प्रेषण अवधि के लिए निजी क्षेत्र के बैंक**
भौतिक	**<u>स्थानीय लेनदेन</u>** टी + 3 कार्य दिवस (पुट-थ्रू तिथि को छोड़कर)	**<u>बाहरी लेनदेन</u>** टी + 5 कार्य दिवस (पुट-थ्रू तिथि को छोड़कर)	टी + 3 दिन (पुट-थ्रू तिथि सहित, रविवार और छुट्टियां सहित)
	दूरस्थ स्थान, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए T + 12 कार्य दिवस (पुट-थ्रू डेट को छोड़कर)		
ई-भुगतान	टी +1 कार्य दिवस (पुट-थ्रू डेट सहित)		टी + 1 कार्य दिवस (पुट-थ्रू डेट सहित)

8.2 यदि उपर्युक्त निर्धारित अवधि से अधिक कोई विलंब होता है, तो बैंक विलंबित अवधि के लिए ब्याज प्रभारित किए जाने के लिए उत्तरदायी होंगे। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है विलंबित अवधि के लिए ब्याज को निर्धारित किया जाना है और जेडएओ द्वारा चूककर्ता बैंक से संग्रहण किया जाना है। प्रभारित की जाने वाली ब्याज दर, प्रचलित बैंक दर +2% होगी है या जैसा कि रिज़र्व बैंक द्वारा समय-समय पर सीजीए के परामर्श से तय किया गया है।

9. "मार्च" लेनदेन का लेखा

9.1 रिज़र्व बैंक, केंद्रीय कार्यालय, मुंबई प्रत्येक वर्ष फरवरी के महीने में मार्च के लेनदेन के लेखा में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में प्रत्यक्ष कर संग्रहण करने वाले सभी बैंकों को विशेष निर्देश जारी करेगा।

9.2 नोडल बैंकों को चालू वर्ष के अप्रैल में पिछले वित्तीय वर्ष के मार्च से संबंधित सूचनाएं प्राप्त होंगी। उसी वित्तीय वर्ष में मार्च के पूरे संग्रह के लिए, नोडल बैंकों को अप्रैल के महीने के दौरान निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करना होगा:

नोडल बैंकों को अलग-अलग स्क्रॉल के दो सेट तैयार करने होते हैं - एक मार्च अवशिष्ट संग्रह (31 मार्च से पहले करदाता के खाते से प्राप्त भुगतान) से संबंधित है और दूसरा अप्रैल में पहले 15 दिनों के दौरान अप्रैल लेनदेन के लिए। उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि 31 मार्च तक प्राप्त करने वाली शाखाओं द्वारा किए गए सभी कर संग्रहों को **"मार्च अवशिष्ट लेनदेन"** के रूप में शामिल किया जाए और इसे अप्रैल के लेनदेन के साथ मिश्रित नहीं किया जाना चाहिए जो वित्तीय वर्ष में पड़ता है। दिनांक 1 से 15 अप्रैल तक तैयार किए गए मार्च लेनदेन के लिए मुख्य स्क्रॉल को स्पष्ट रूप से **"मार्च अवशिष्ट"** के रूप में चिह्नित किया जाना है।

9.3 यह भी ध्यान दिया जाना चाहिए कि 31 मार्च को या उससे पहले भुगतान किए गए सभी चेकों/राशि को चालू वित्तीय वर्ष से संबंधित लेनदेन के रूप में माना जाना चाहिए और चालू वित्त वर्ष में **"मार्च या मार्च अवशिष्ट लेनदेन"** शीर्षक के तहत इस तरह से हिसाब रखा जाना चाहिए।

9.4 नागपुर में अपने लिंक सेल को रिपोर्ट करते समय, नोडल बैंकों को 15 अप्रैल तक अलग-अलग मार्च अवशिष्ट और अप्रैल लेनदेन को दर्शाने वाले आंकड़ों के दो सेट भेजने चाहिए।

9.5 तिथि-वार मासिक विवरण भी दो सेटों में तैयार किए जाने चाहिए, एक **मार्च अवशिष्ट लेनदेन** से संबंधित और दूसरा **अप्रैल लेनदेन** से संबंधित।

10. हर साल मार्च के महीने के दौरान विशेष व्यवस्था

शाखाओं को पहले पैराग्राफ में बताई गई प्रक्रिया का सावधानीपूर्वक पालन करना चाहिए और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्यक्ष करों के लिए किए गए संग्रह को नोडल शाखा / लिंक सेल के माध्यम से सरकारी खाते में क्रेडिट के लिए तुरंत पारित किया जाए। तथापि, प्रत्येक वर्ष मार्च के दूसरे पखवाड़े के दौरान, जहां भी प्राप्तकर्ता शाखाएं और नोडल शाखा स्थानीय रूप से स्थित हैं, प्राप्त करने वाली शाखाओं द्वारा एक विशेष संदेशवाहक प्रणाली शुरू की जानी चाहिए। प्रत्येक वर्ष जून, सितम्बर और दिसम्बर के दूसरे पखवाड़े के दौरान जेडएओ को दैनिक आधार पर संग्रहण आंकड़े उपलब्ध कराने के लिए भी सभी प्रयास किए जाएं ताकि निगरानी, प्राक्कलन आदि के लिए सरकार को आगे से पारेषण किया जा सके।

11. निगरानी समिति - आवधिक बैठकों का आयोजन

प्राधिकृत बैंकों द्वारा प्रत्यक्ष करों के संग्रहण और लेखांकन के लिए संशोधित योजना के सुचारू संचालन के लिए, प्रत्येक क्षेत्रीय लेखा कार्यालय केंद्र पर नोडल बैंकों/बैंकों के स्थानीय प्राधिकरणों, जेडएओ और आयकर विभाग के अधिकारियों को शामिल करते हुए निगरानी समितियों का गठन किया जाएगा। समिति छमाही बैठक करेगी और प्रत्यक्ष कर कार्य से जुड़े विभिन्न मुद्दों जैसे लेखांकन, स्क्रॉलिंग, रिपोर्टिंग, प्रेषण और सुलह आदि पर चर्चा करेगी और अपने स्तर पर समस्याओं को हल करने के प्रयास करेगी। इसके अलावा, सालाना एक विशेष निगरानी समिति की बैठक होगी जिसमें सीबीडीटी, आरबीआई, आयकर विभाग और बैंकों के बहुत वरिष्ठ अधिकारी भाग लेंगे और क्षेत्रों में बैंकों, जेडएओ और आयकर विभाग के सामने आने वाली विभिन्न समस्याओं का निवारण करेंगे। बैंक यह सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त पर आवश्यक अनुवर्ती कार्रवाई की जाए।

12. सार्वजनिक शिकायतों का निवारण

प्रत्येक प्राधिकृत बैंक के पास समय-समय पर निर्धारित सरकारी विभागों या जनता के सदस्यों को सेवा प्रदान करने वाली शाखाओं में सार्वजनिक शिकायतों से निपटने के लिए एक प्रभावी प्रक्रिया होनी चाहिए। यदि बैंक को कर भुगतान की रिपोर्टिंग में गड़बड़ी का पता चलता है या कर भुगतान के प्रमुख प्रमुख को या तो स्वत: संज्ञान में लाया जाता है या करदाता द्वारा उसके ध्यान में लाया जाता है, तो बैंक तुरंत त्रुटि रिकॉर्ड (जैसा कि पैरा 2.6 और 7.4 में पहले वर्णित है) को टिन को प्रेषित करेगा। यह जरूरी है क्योंकि आयकर विभाग बैंक द्वारा टिन को प्रेषित जानकारी पर करदाता को क्रेडिट देगा।

****

ओएलटीएएस

फ़ाइल पृथक्करण सुविधा के लिए उपयोगकर्ता मैनुअल (एफ़एसयू)

परिचय

एफएसयू का उपयोग बैंकों द्वारा अमान्य इनपुट फ़ाइल और संबंधित त्रुटि फ़ाइल से एक वैध फ़ाइल उत्पन्न करने के लिए किया जाएगा। यह उपयोगकर्ता मैनुअल बैंक उपयोगकर्ताओं को इस फ़ाइल पृथक्करण सुविधा में प्रदान की गई कार्यक्षमताओं को बेहतर ढंग से समझने में सक्षम करेगा।

इच्छित उपयोगकर्ता:

यह मैनुअल ओएलटीएएस में भाग लेने वाले बैंकों के लिंक सेल के लिए अभिप्रेत है।

प्रचलित प्रथाएं

प्रत्येक फ़ील्ड या बटन के बारे में विस्तृत जानकारी प्रत्येक कार्य के बाद फ़ील्ड विवरण तालिका में उपलब्ध है .

1. विवरण

एफएसयू एक यूटिलिटी है जो गलत रिकॉर्ड को हटाकर एक वैध ओएलटीएएस फ़ाइल बनाने में मदद करती है। यदि आपके पास एक ओएलटीएएस फ़ाइल और उससे संबंधित त्रुटि फ़ाइल है, तो यह सुविधा आपको गलत रिकॉर्ड से छुटकारा पाने और एक नई सही फ़ाइल बनाने में मदद करेगी। यह त्रुटि फ़ाइल को पढ़कर अस्वीकृत रिकॉर्ड को हटा देता है और एक नई फ़ाइल उत्पन्न करता है जिसमें केवल स्वत: उत्पन्न आरटी04 रिकॉर्ड के साथ मान्य रिकॉर्ड होते हैं। यह सही फ़ाइल ओएलटीएएस साइट पर अपलोड किया जा सकता है। सभी अस्वीकृत रिकॉर्ड अलग किए जाते हैं और आपके संदर्भ के लिए अन्य फ़ाइल में रखे जाते हैं।

2. **क्रियात्मकता:** जब आप स्पेशल_एफ़वीयू.ईएक्सई फ़ाइल खोलते हैं तो एक यूटिलिटी नीचे दिखाई देगी।

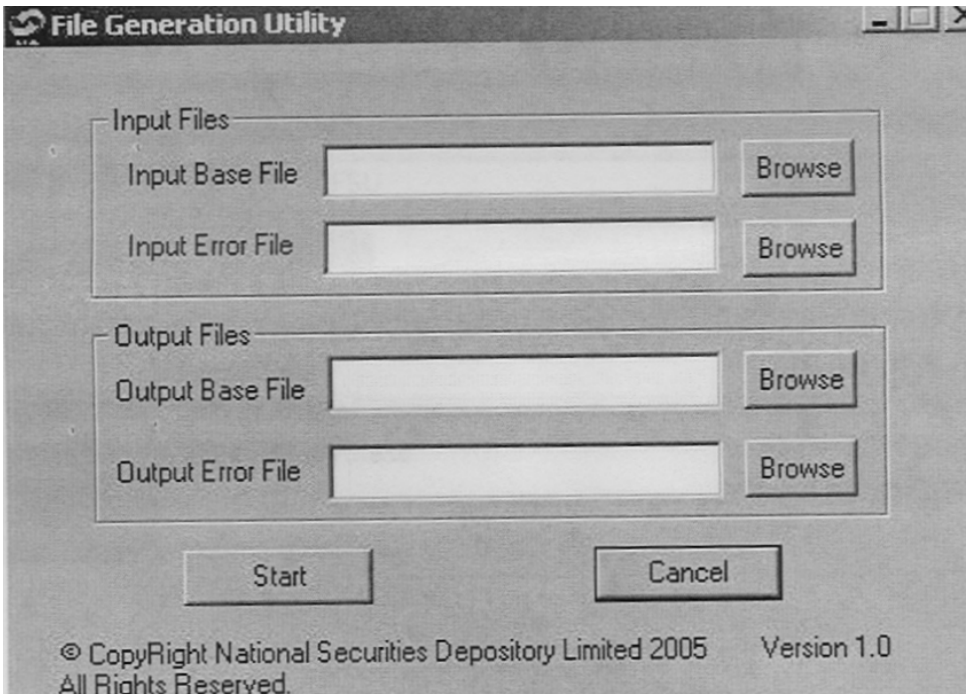

चित्र 1

यूटिलिटी में शीर्ष पर यूटिलिटी का नाम, यूटिलिटी को कम करने और बंद करने के लिए बटन, चार पाठ (टेक्स्ट) फ़ील्ड और "ब्राउज़" नामक चार बटन, एक स्टार्ट बटन और एक रद्द बटन शामिल हैं। एक कॉपीराइट संदेश और संस्करण संख्या भी दिखाई देगी।

उपयोगकर्ता को नीचे वर्णित सभी चार टेक्स्ट फ़ील्ड में मान्य इनपुट दर्ज करना आवश्यक है।

A. इनपुट आधार फ़ाइल:

आधार फ़ाइल का पूर्ण फ़ाइल पथ दें। यह आधार फ़ाइल वह फ़ाइल है जिसे कुछ त्रुटियों के कारण अस्वीकार कर दिया गया है। आप ब्राउज़ बटन पर क्लिक करके फ़ाइल का चयन कर सकते हैं। यह आपको नीचे प्रदर्शित एक 'ओपन' बॉक्स दिखाएगा (चित्रा 2)। आवश्यक फ़ोल्डर के लिए ब्राउज़ करें, फ़ाइल का चयन करें और फिर 'ओपन' पर क्लिक करें.

इनपुट फ़ाइल नाम केवल "ddmmyyfv.bnk" प्रारूप में होना चाहिए।

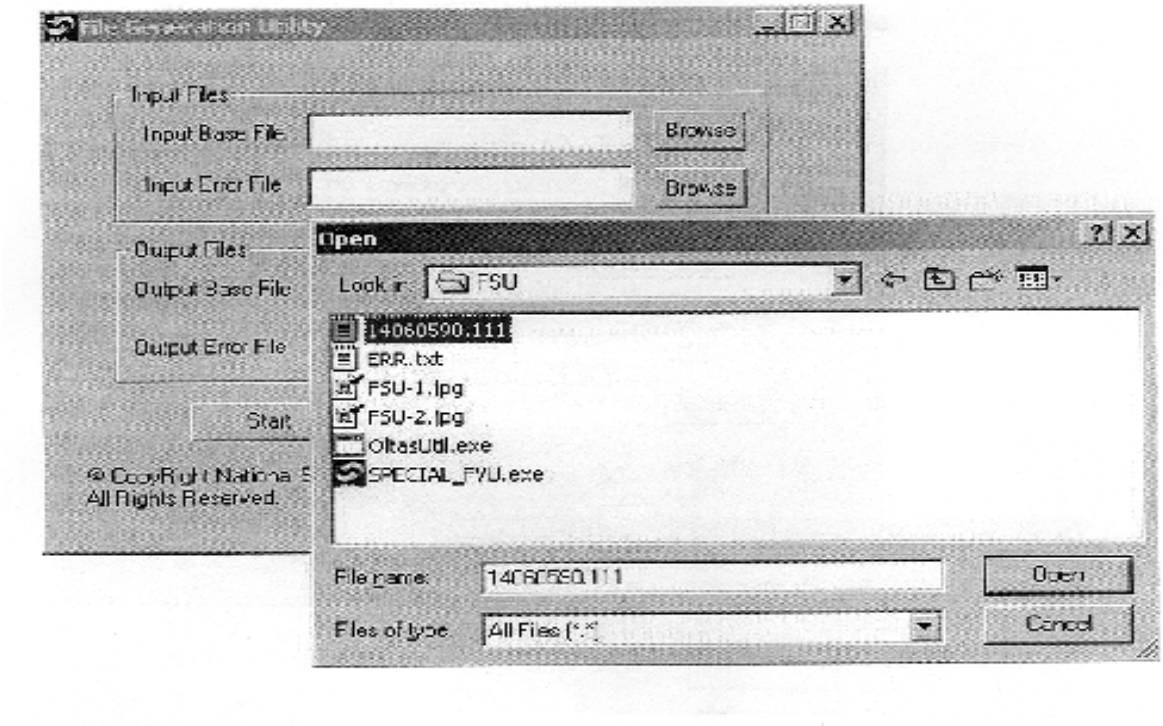

चित्र 2

फाइलई एक्सटेंशन में बैंक का वैध कोड होना चाहिए।

B. इनपुट त्रुटि फ़ाइल:

यह इनपुट आधार फ़ाइल (चरण 1 में चुना गया) के लिए त्रुटि है। त्रुटि फ़ाइल ओएलटीएएस साइट से डाउनलोड किया जा सकता है और से सेव किया जा सकता है। आप ओएलटीएएस लिंक सेल सुविधा द्वारा उत्पन्न त्रुटि फ़ाइल का भी उपयोग कर सकते हैं। आपको त्रुटि फ़ाइल का पूरा पथ देने की आवश्यकता है। दाईं ओर ब्राउज़ बटन का उपयोग ऊपर बताए अनुसार किया जा सकता है। त्रुटि फ़ाइल में वह फ़ाइल नाम है जिसके लिए त्रुटियाँ पाई जाती हैं। यह नाम इनपुट आधार फ़ाइल से मेल खाना चाहिए। उपयोगकर्ता को इस फ़ाइल को नहीं बदलना चाहिए। इसके अलावा यदि सही त्रुटि फ़ाइल का उपयोग नहीं किया जाता है, तो निम्नलिखित संदेश दिखाया जाएगा और यूटिलिटी बंद हो जाएगी (चित्रा 3)।

इनपुट त्रुटि फ़ाइल के नाम के लिए कोई सत्यापन नहीं है।

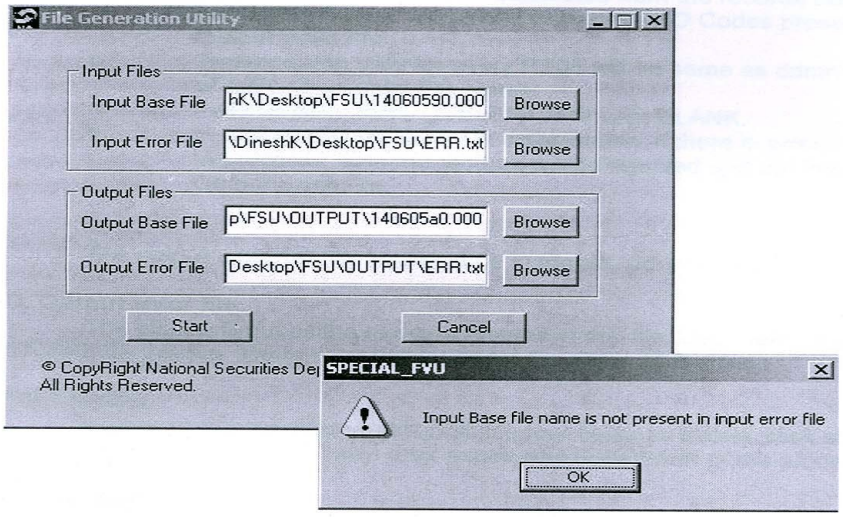

Figure 3

नोट: यदि दो इनपुट फ़ाइलों में से किसी एक के साथ छेड़छाड़ की गई है तो आउटपुट मान्य फ़ाइल ठीक से जनरेट नहीं होगी। इसके अलावा एफ़वीयू से उत्पन्न या ओएलटीएएस साइट से प्राप्त त्रुटि फ़ाइल स्वीकार्य है। किसी अन्य प्रारूप का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वे गलत परिणाम दे सकते हैं।

C. आउटपुट आधार फ़ाइल:

यह आउटपुट मान्य फ़ाइल है जिसे ओएलटीएएस साइट पर अपलोड किया जा सकता है या एफ़वीयू के माध्यम से मान्य किया जा सकता है। फ़ाइल का पूर्ण पथ निर्दिष्ट करने की आवश्यकता है। फ़ाइल नाम इनपुट बेस फ़ाइल नाम के समान हो सकता है यदि स्थान अलग है अन्यथा यह इनपुट बेस फ़ाइल पर अधिलेखित हो जाएगा। आवश्यक फ़ोल्डर में ब्राउज़िंग के लिए ब्राउज़ बटन का उपयोग करें और तब आवश्यक फ़ाइल नाम दर्ज करें। इनपुट आधार फ़ाइल और आउटपुट आधार फ़ाइल का विस्तार मेल खाना चाहिए।

a. RT04 में फ़ील्ड MAJ_HD_CD,TOT_NO_OF_RFND,TOT_NO_OF_CHLN, TOT_NO_ERR_RFND, TOT_NO_ERR_CHLN, RFND_TOT_AMT, CHLN_TOT_AMT की गणना आउटपुट मान्य फ़ाइल में मौजूद रिकॉर्ड डेटा से की जाती है।
b. No_Of_Nodal फ़ील्ड की गणना आउटपुट मान्य फ़ाइल में मौजूद रिकॉर्ड डेटा से की जाएगी यानी आउटपुट मान्य फ़ाइल में मौजूद अलग-अलग जेडएओ कोड द्वारा।
c. प्रत्येक RT04 के लिए ट्रांसमिशन दिनांक आउटपुट मान्य फ़ाइल नाम के ddmmy भाग के समान होगी.
d. RT04 का फ़ील्ड RFND_DEBIT_DT रिक्त रखा गया है.
e. एक विशेष RT08 R / N संयोजन में, यदि किसी भी रिकॉर्ड में त्रुटि है, तो दोनों रिकॉर्ड अस्वीकार कर दिए जाएंगे और आउटपुट त्रुटि फ़ाइल में डाल दिए जाएंगे।

आउटपुट आधार फ़ाइल नाम प्रारूप "ddmmyyfv.bnk" में होना चाहिए

D. आउटपुट त्रुटि फ़ाइल:

यूटिलिटी इस फ़ाइल में सभी अस्वीकृत रिकॉर्ड डाल देगी। उपयोगकर्ता को इस फ़ाइल के लिए पूरा पथ देने की आवश्यकता है। इस फ़ाइल के नाम के लिए कोई सत्यापन नहीं है.

प्रारंभ बटन:

उपरोक्त सभी चार फ़ील्ड में मान्य फ़ाइल नाम दर्ज करने के बाद, प्रारंभ बटन क्लिक करें। प्रक्रिया के सफल समापन के बाद एक संदेश दिखाया जाएगा।

रद्द करें बटन: यूटिलिटि बंद करने के लिए रद्द करें बटन का उपयोग करें।

अनुबंध III

<u>नोडल शाखा दैनिक मुख्य स्क्रॉल (रसीदें) का प्रारूप</u>

1	नोडल शाखा स्क्रॉल दिनांक (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई)
2	बीएसआर कोड
3	शाखा स्क्रॉल प्राप्त करने की तिथि (डीडी / एमएम / वाईवाईवाईवाई)
4	कुल कर राशि
5	चालान की कुल संख्या
6	डीओ-आईडी

पहले छह फ़ील्ड

#	प्रमुख शीर्ष
#	राशि
#	चालानों की संख्या

ब्लॉक

#	प्रमुख शीर्ष
#	राशि
#	चालानों की संख्या

ब्लॉक

#	प्रमुख शीर्ष
#	राशि
#	चालानों की संख्या

:
:
:

यह ब्लॉक (ऊपर दिखाया गया है) को उतनी बार दोहराया जाएगा जितनी बार कर शीर्ष उपलब्ध हैं।

नोट:

1) एक प्राप्त शाखा के लिए रिकॉर्ड एक पंक्ति में निहित होना चाहिए और मूल्यों को अल्पविराम से अलग किया जाना चाहिए।

2) कैरिज रिटर्न या लाइनफीड [यानी एंटर कुंजी ()] एक प्राप्त शाखा के लिए रिकॉर्ड के अंत को इंगित करता है।

3) ब्लॉक का अनुक्रम (majhd, amt, no_challan) आवश्यक नहीं है लेकिन बढ़ता क्रम बेहतर है।

4) उदाहरण:

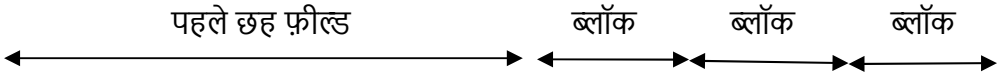

30/11/2005, 0230001, 25/11/2005, 6600, 22, PNE, 0020, 200, 2, 0021, 100, 1, 0024, 300, 4,

0026, 400, 2, 0031, 500, 1, 0032, 600, 2, 0033, 700, 1, 0034, 800, 1,

0070, 900, 1, 0036, 1100, 5

विस्तृत उदाहरण

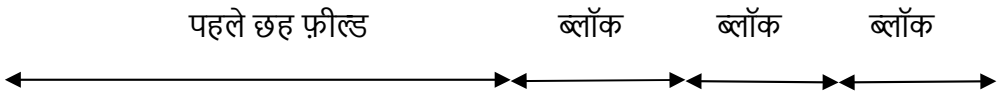

13/11/2005, 0000455, 12/11/2005, 5775, 18, PNE, 0020, 1525, 6, 0021, 200, 2, 0023, 100, 1, 0026, 300, 2, 0031,

600, 1, 0032, 750, 2, 0033, 550, 1, 0034, 800, 2, 0070, 950, 1

13/11/2005, 0003861, 12/11/2005, 9950, 17, PNE, 0020, 3500, 5, 0020, 2250, 3, 0023, 300, 1, 0026, 400, 1, 0031,

500, 1, 0033, 600, 2, 0032, 700, 1, 0034, 800, 2, 0070, 900, 1

13/11/ 2005, 0004618, 11/11/2005, 640112, 22, PNE, 0020, 629367, 20, 0021, 10745, 2

13/11/2005, 0230011, 11/11/2005, 47071, 2, PNE, 0020, 47071, 2

13/11/2005, 0230116, 10/11/2005, 304648, 20, NSK, 0020, 26942, 2, 0021, 277706, 18

13/11/2005, 0230004, 13/11/2005, 408134, 16, NSK, 0020, 407190, 15, 0021, 944, 1

5) यदि नोडल बैंक एक डीआरएस में एक ही प्राप्त शाखा के लिए दो अलग-अलग तिथियों के स्क्रॉल भेज रहा है, तो उनकी प्रविष्टि डीआरएस फ़ाइल में दो अलग-अलग लाइनें होनी चाहिए जैसा कि नीचे दिखाया गया है:

14/11/2005, 0002053, 12/11/2005, 5775, 18, PNE, 0020, 1525, 6, 0021, 200, 2, 0023, 100, 1, 0026, 300, 2, 0031,

600, 1, 0032, 750, 2, 0033, 550, 1, 0034, 800, 2, 0070, 950, 1

14/11/2005, 0002053, 13/11/2005, 9950, 17, PNE, 0020, 5250, 6, 0023, 500, 2, 0024, 300, 1, 0025, 400, 1, 0031,

500, 1, 0033, 600, 2, 0033, 700, 1, 0034, 800, 2, 0070, 900, 1

14/11/2005, 0002034, 13/11/2005, 408134, 16, NSK, 0020, 407190, 15, 0021, 944, 1

- उपरोक्त डीआरएस की पहली दो पंक्तियों का निरीक्षण करें जिसमें दोनों लाइनों में एक ही नोडल शाखा स्क्रॉल तिथि और बीएसआर कोड है, जो इस मामले में आवश्यक है, लेकिन विवरण अलग-अलग हैं।
- शाखा स्क्रॉल प्राप्त करने की तिथि अलग है जो नोडल शाखा स्क्रॉल तिथि से कम होनी चाहिए।
- तीसरी पंक्ति उसी नोडल बैंक की अन्य शाखा के लिए नियमित पंक्ति है।

6) दिनांक: DD/MM/YYYY प्रारूप में दिनांक है।

BSR कोड: 7 अंकों का संख्यात्मक कोड है।

DO-ID: 3-अंकीय अल्फा कोड है।

प्रमुख शीर्ष: 4 अंकों का संख्यात्मक कोड है।

चालान की राशि और संख्या संख्यात्मक मान हैं।

****

करदाताओं को बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले कंप्यूटर जनित रसीदों का प्रारूप प्रोफार्मा

कंप्यूटर जनित रसीद (बैंक शाखा द्वारा प्रत्यक्ष कर के जमाकर्ता को चालान फॉर्म संख्या 281 के विरूद्ध स्रोत पर काटे गए कर को सरकारी खाते में जमा करने के लिए जारी किया जाएगा)	
कर वसूलने वाले बैंक का नाम	
कटौतीकर्ता का पूरा नाम	
कटौतीकर्ता का टैन (**10** वर्ण)	
जमा की गई राशि:	
(i) आयकर	
(ii) अधिभार	
(iii) शिक्षा उपकर	
(iv) दण्ड	
जमा की गई कुल राशि: (आंकड़े में)	
कर जमा करने का तरीका (नकद/ खाते से नामे/ चेक (जिसकी संख्या) द्वारा)	
चेक के नकदीकरण की तिथि (dd/mm/yy)	
आयकर कटौती/संग्रह के कारण कंपनियां (**0020**)/ कंपनियों के अलावा अन्य (**0021**)	
लघु शीर्ष - भुगतान का प्रकार - (टीडीएस / टीसीएस काटा गया / कटौतीकर्ता द्वारा संग्रहण किया गया या विभाग द्वारा मांग की गई)	**200/400**
भुगतान की प्रकृति जिसमें से कर काटा या एकत्रित किया गया - (अनुभाग कोड दें)	
आकलन वर्ष (yy)	
चालान पहचान संख्या (सीआईएन)	
बैंक शाखा संग्रहण करने का बीएसआर कोड (**7** अक्षर)	
चेक की जमा की तिथि (dd/mm/yy) (**8** अक्षर)	
चालान क्रम संख्या (**5** अक्षर)	

संग्रहण करने वाली बैंक शाखा के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर

↓

करदाताओं को बैंकों द्वारा जारी किए जाने वाले कंप्यूटर जनित रसीदों का प्रोफार्मा

कंप्यूटर जनित रसीद (बैंक शाखा द्वारा प्रत्यक्ष कर के जमाकर्ता को चालान फॉर्म संख्या **280** के विरुद्ध स्रोत पर काटे गए कर को सरकारी खाते में जमा करने के लिए जारी किया जाएगा)	
कर वसूलने वाले बैंक का नाम	
करदाता का पूरा नाम	
करदाता का पैन (**10** अक्षर)	
जमा की गई राशि:	
(i) आयकर	
(ii) अधिभार	
(iii) शिक्षा उपकर	
(iv) दण्ड	
जमा की गई कुल राशि: (आंकड़े में)	
कर जमा करने का तरीका (नकद/ खाते से नामे// चेक द्वारा (जिसकी संख्या))	
चेक के नकदीकरण की तिथि (dd/mm/yy)	
आयकर कटौती/संग्रह के कारण कंपनियां (**0020**)/ कंपनियों के अलावा अन्य (**0021**)	
लघु शीर्ष - भुगतान का प्रकार	
आकलन वर्ष (yy)	
चालान पहचान संख्या (सीआईएन)	
संग्रहण करने वाली बैंक शाखा का बीएसआर कोड (**7** अक्षर)	
चेक की जमा की तिथि (dd/mm/yy) (**8** अक्षर)	
चालान क्रम संख्या (**5** अक्षर)	
संग्रहण करने वाली बैंक शाखा के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर	

मैं घर/कार्यालय में बैठकर ऑनलाइन कर भुगतान कैसे कर सकता हूं?

ऊपर सूचीबद्ध किसी भी बैंक के साथ नेट-बैंकिंग खाता खोलें।

i. incometaxindia.gov.in वेबसाइट पर जाएं, 'करों का ऑनलाइन भुगतान करें' पर क्लिक करें।
ii. आवश्यक चालान ऑनलाइन भरें। मदद स्क्रीन पर अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, डाउनलोड आदि के रूप में उपलब्ध है।
iii. नेट-बैंकिंग खाते के माध्यम से ऑनलाइन कर भुगतान करें।
iv. एक चालान काउंटरफॉइल सीआईएन (चालान पहचान संख्या) के साथ स्क्रीन पर तुरंत उपलब्ध होगा। इस काउंटरफॉइल पर चालान पहचान संख्या (सीआईएन) को आय विवरणी में उद्धृत किया जाना चाहिए।
v. यदि संभव हो तो काउंटरफॉइल प्रिंट करें और इसे कंप्यूटर में भी सहेजें।
vi. आपका भुगतान आयकर विभाग के पास पहुँचने का पता लगाने के लिए। https://tin.tin.nsdl.com/oltas/servlet/QueryTaxpayer लिंक पर क्लिक करें

"...","..."...".

करों का ऑनलाइन भुगतान करने के क्या फायदे हैं?

i. आप अपने नेट-बैंकिंग खाते के माध्यम से किसी भी समय किसी भी स्थान से करों का भुगतान कर सकते हैं।
ii. अपने खाते से धन का त्वरित हस्तांतरण।
iii. ई-चालान पर आप जो लिखेंगे वह सीधे आयकर विभाग को भेजा जाएगा। बैंक कोई डेटा एंट्री नहीं करेंगे।
iv. आप चालान कॉपी और रसीद कॉपी को सेव/प्रिंट कर सकते हैं।
v. जैसे ही आपका बैंक राशि के भुगतान को अधिकृत करता है, आपको अपने बैंक से एक स्पष्ट, सुस्पष्ट रसीद / काउंटरफॉइल प्राप्त होगा।
vi. ई-पेमेंट ट्रांजेक्शन की ट्रांजैक्शन आईडी आपके बैंक स्टेटमेंट में आपके लिए उपलब्ध होगी।
vii. आप ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि आपका पैसा वास्तव में आयकर विभाग में पहुंचा है या नहीं। इसके लिए आपको टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क वेबसाइट पर जाना होगा:

https://tin.tin.nsdl.com/oltas/index.html

और इस बॉक्स पर क्लिक करना होगा | सीआईएन आधारित दृश्य |

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया: incometaxindia.gov.in **वेबसाइट पर करों का ऑनलाइन भुगतान करें देखें।**

: बकाया मांग के विरूद्ध समायोजित रिफंड के मामले में, सामान्य रिफंड चालान के साथ संलग्न किया जाना चाहिए और पहले की प्रक्रिया के अनुसार एओ द्वारा बैंक को भेजा जाना चाहिए**।**

मास्टर परिपत्र - सूचकांक

क्रम सं.	संदर्भ सं.	विषय
1.	डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-684/42.01.001/2003-04 दिनांक 9 जनवरी 2004	पिंक बुक में संशोधन 'प्रत्यक्ष करों के लिए लेखा प्रणाली'
2.	आरबीआई/2004/135 डीजीबीए. जीएडी. सं.1142/42.01.001/2003-04 दिनांक 2 अप्रैल, 2004	बैंक शाखाओं में करों के संग्रह की प्रक्रिया - ग्राहक सेवा
3.	आरबीआई/2004/131 डीजीबीए. जीएडी. सं.1008/42.01.034/2003-04 दिनांक 1 अप्रैल, 2004	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) की शुरुआत - चालान की प्रतियों पर रबर स्टैंप की ब्रांडिंग
4.	आरबीआई/2004/145 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-1068/42.01.034/2003-04 दिनांक 16 अप्रैल, 2004	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) के लिए लेखा प्रक्रिया
5.	आरबीआई/2004/184 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-1114/42.01.034/2003-04 दिनांक 29 अप्रैल, 2004	1 जून, 2004 से ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली का कार्यान्वयन
6.	आरबीआई/2004/75 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-69/42.01.034/2004-05 दिनांक 28 जुलाई 2004	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - एनएसडीएल को डेटा का प्रसारण - सत्यापन जांच
7.	डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-8649/42.01.034/2005-06 दिनांक 23 दिसम्बर 2005	ऑन-लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) - बैंकों में सॉफ्टवेयर सत्यापन
8.	आरबीआई/2006/295 डीजीबीए. जीएडी. संख्या 11140/42.01.034/2005-06 दिनांक 2 फ़रवरी 2006	ऑन-लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) - ZAOs को ई-मेल द्वारा दैनिक स्क्रॉल भेजना
9.	आरबीआई/2004/326 डीजीबीए. जीएडी. सं.3278-3311/42.01.034/ 2004-05 दिनांक 31 दिसम्बर 2004	सीबीडीटी बकाया के संग्रह के लिए उप-एजेंसी व्यवस्था का उन्मूलन
10.	आरबीआई/2005/466 डीजीबीए. जीएडी. सं.एच.5801/42.01.034/2004-05 दिनांक 13 मई 2005	ऑन-लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) – फंड सेटलमेंट
11.	आरबीआई/2005/406 डीजीबीए. जीएडी. सं.एच.5236/42.01.034/2004-05 दिनांक 29 मार्च, 2005	ऑन-लाइन टैक्स अकाउंटिंग एससिस्टम (ओएलटीएएस) - फंड सेटलमेंट - आरबीआई, सीएएस नागपुर को रिपोर्टिंग
12.	आरबीआई/2004/213 डीजीबीए. जीएडी. सं.एच - 1169/42.01.034/ 2003-04 दिनांक 22 मई 2004	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) से संबंधित लेखा प्रक्रिया - स्पष्टीकरण

13.	आरबीआई/2004/181 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-235/42.01.034/2004-05 दिनांक 15 सितम्बर 2004	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - शाखाओं की भागीदारी
14.	आरबीआई/2004/164 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-170/42.01.034/2003-04 दिनांक 4 सितंबर, 2004	बैंकों द्वारा ओएलटीएएस डेटा के डेटा कैप्चर के बारे में महत्वपूर्ण मुद्दे
15.	आरबीआई 2005/412 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-5318/42.01.034/2004-05 दिनांक 4 अप्रैल, 2005	प्रत्यक्ष करों के संग्रह के लिए बैंक शाखाओं का अधिकार रद्द
16.	आरबीआई/2005/81 डीजीबीए. जीएडी. सं.382/42.01.034/2005-06 दिनांक 26 जुलाई 2005	ओएलटीएएस - कर सूचना नेटवर्क (TIN) द्वारा विकसित फ़ाइल पृथक्करण यूटिलिटी
17.	आरबीआई/2005/411 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-5287/42.01.034/2004-05 दिनांक 1 अप्रैल, 2005	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली (ओएलटीएएस) - CBDT संग्रह को सरकारी खातों में जमा करने से संबंधित लेखा प्रक्रिया
18.	आरबीआई/2006/150 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-6226/42.01.011/2006-07 दिनांक 10 अक्टूबर, 2006	सरकारी राजस्व के प्रेषण की अनुमेय अवधि
19.	आरबीआई/2007/235 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-11763/42.01.011/2006-07 दिनांक 24 जनवरी 2007	सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी - विलंबित अवधि ब्याज
20.	आरबीआई/2007/286 डीजीबीए. जीएडी. सं.13742/42.01.011/2006-07 दिनांक 13 मार्च, 2007	सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी - विलंबित अवधि ब्याज
21.	डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-8294/42.01.037/2005-06 दिनांक 14 दिसम्बर 2005	ऑन-लाइन कर लेखा प्रणाली – चेक प्राप्त करना करदाता - भुगतानकर्ता का नाम
22.	आरबीआई/2005/39 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-42/42.01.034/2005-06 दिनांक 4 जुलाई 2005	वित्त अधिनियम 2005- प्रमुख शीर्ष और चालान में परिवर्तन
23.	आरबीआई/2006/55 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-161/42.01.034/2005-06 दिनांक 7 जुलाई 2006	ओएलटीएएस - पैन / टैन का सत्यापन
24.	आरबीआई/2004/300 डीजीबीए. GAD.सं.. एच.2532-65/42.01.034/2004-05 दिनांक 14 दिसम्बर 2004	दिनांक 1-1-2005 से चालान पर स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य रूप से उल्लेख करना

25.	आरबीआई/2005/265 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-8824/42.01.034/2005-06 दिनांक 28 दिसम्बर 2005	स्थायी खाता संख्या (पैन)/कर कटौती खाता संख्या (टैन) का अनिवार्य उल्लेख - राजस्थान राज्य
26.	डीजीबीए. जीएडी. सं.3774/42.01.034/2007-08 दिनांक 9 अक्टूबर 2007	टिन पर अपलोड किए गए चालान विवरण में विसंगतियां
27.	आरबीआई/2007/206 डीजीबीए. जीएडी. सं.6212/42.01.034/2007-08 दिनांक 6 दिसम्बर 2007	ऑन-लाइन टैक्स अकाउंटिंग सिस्टम (ओएलटीएएस) - डेटा गुणवत्ता की चिंताएं
28.	आरबीआई/2008/328 डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच-12070/42.01.034/ 2007-08 दिनांक 22 मई 2008	डेटा की गुणवत्ता में सुधार - 1-2011 से कम्प्यूटरीकृत प्राप्तियों की शुरूआत. 1 जून 2008
29.	आरबीआई/2008/275 डीजीबीए. जीएडी. सं.10577/42.01.038/2007-08 दिनांक 3 अप्रैल, 2008	सरकारी राजस्व से संबंधित ई-भुगतान लेनदेन के लिए कट-ऑफ समय
30.	आरबीआई/2008/280 डीजीबीए. जीएडी. एच-10875/42.01.038/ 2007-08 दिनांक 10 अप्रैल, 2008	करदाताओं की कुछ श्रेणियों द्वारा कर का अनिवार्य ई-भुगतान 01.04.2008 से
31.	आरबीआई/2008/321 डीजीबीए. जीएडी. एच-11895/42.01.038/ 2007-08 दिनांक 15 मई 2008	आईटी अधिनियम की धारा 44एबी के तहत आने वाले कॉर्पोरेट और करदाताओं द्वारा प्रत्यक्ष करों का अनिवार्य ई-भुगतान
32.	डीजीबीए. जीएडी. सं.एच.551/42.01.011/2008-09 दिनांक 18 जुलाई 2008	सरकारी लेन-देन के ई-भुगतान के विप्रेषण की अनुमेय अवधि – निजी क्षेत्र के बैंक
33.	आरबीआई/2010-11/229 डीजीबीए. जीएडी. नहीं.एच. 2444/42.01.011/2010-11 दिनांक 8 अक्टूबर, 2010	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा सरकारी खाते में ई-भुगतान के प्रेषण के लिए अनुमेय अवधि
34.	आरबीआई/2009/463 डीजीबीए. जीएडी संख्या एच -9284/42.01.011/2008-09 दिनांक 28 अप्रैल 2009	सरकारी खातों में सरकारी प्राप्तियों के प्रेषण में देरी पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों से ब्याज की वसूली
35.	आरबीआई/2009-10/381 डीजीबीए. जीएडी संख्या एच 7790/42.01.011/2009-10 दिनांक 6 अप्रैल, 2010	दूरस्थ इलाकों, दुर्गम और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए सरकारी खाते में सरकारी राजस्व के प्रेषण के लिए अनुमेय अवधि

36.	आरबीआई/2014-15/416 (डीजीबीए. जीएडी. संख्या एच -3203/42.01.011/2014-15) दिनांक 21 जनवरी, 2015)	डेबिट / क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग के माध्यम से सरकारी खाते में प्रेषण के लिए अनुमेय अवधि